असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 फरवरी, 2020

षोडश विधान सभा | बुधवार, तिथि 26 फरवरी, 2020 ई0
पंचदश सत्र | 07 फरवरी, 2020 (श0)

कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

प्रश्नोत्तर काल

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य-स्थगन है ।

अध्यक्ष : कार्य-स्थगन के समय में न । ठीक है । आप कार्य-स्थगन के समय में उठाईयेगा । हम आपका सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आपका विषय महत्वपूर्ण है तो क्या माननीय सिद्दिकी साहब का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है ?

(व्यवधान जारी)

आपलोग कार्य-स्थगन सूचना देने के समय पर उठाईयेगा । आसन सुनेगा। श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या : 4 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला जागरण केन्द्र और एक्शन एड से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजनों में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करनेवाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों पर परिवर्तनशील मंगगाई भत्ता की दरें वर्ष में 02 बार निर्धारित की जाती है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानेवाली दरें महिला एवं पुरूष श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू की जाती है एवं इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत महिला कामगारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, समान पारिश्रमिक की व्यवस्था, शिशु कक्ष की व्यवस्था, मातृत्व

टर्न-1/कृष्ण/26.02.2020/

प्रसुविधा की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भी है । किसी सभी नियोजक के लिये अधिनियमों के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना बाध्यकारी है । समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976 के अन्तर्गत स्त्री एवं पुरूष के लिए बिना भेद-भाव के समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक की व्यवस्था एवं लैंगिक आधार पर बिना किसी भेद-भाव के नियोजन (भर्ती) का प्रावधान है ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत बिन्दु पर किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया दर न्यूनतम मजदूरी अधिनिमय,1948 के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

राज्य सरकार विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने हेतु कृत-संकल्पित है एवं किसी भी शिकायत की स्थिति में उस पर श्रम अधिनियमों के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई भी की जाती है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप अपने सीट पर जाकर समय पर अगर इस मुद्दे को उठाईयेगा तो इसका कुछ निराकरण होगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश बाबू, कांग्रेस के इतने पुराने लीडर हैं और महोदय, इनको नियमावली की जानकारी है, जो प्रश्न काल है महोदय, मैं देख रहा हूं कि अल्पसूचित प्रश्न से लेकर तारांकित प्रश्न भी जितने हैं, 1, 2, 3 तारांकित प्रश्न लगातार विपक्ष के माननीय सदस्यों का है । तो ये प्रश्न क्यों डालते हैं, जब इनको पूछने का समय नहीं है ? इनको जवाब लेने का समय नहीं है तो प्रश्न क्यों पूछते है ? महोदय, इनका मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, ये अखबार और मीडिया में जाना चाहते हैं । इनको बिहार के प्रश्नों से मतलब नहीं है और कितनी तैयारी के साथ माननीय सदस्यों ने प्रश्न डाले हैं और कितनी तैयारी के साथ सरकार आयी है और ये जवाब नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं । महोदय, बिहार की जनता देख रही है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाय और प्रश्न पूछें और सरकार उसका उत्तर देगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अगर समय पर बात उठाईयेगा तब न हम कुछ सुनकर कहेंगे । आप तो वेल में खड़ा होकर टेबल पकड़कर बोल रहे हैं । ऐसे में कैसे सुनेंगे ? आप अपनी जगह पर तो पहले जाईये ।

वेल में टेबल पकड़कर कही गयी बात का संज्ञान आसन कैसे लेगा ? आप सीट पर जा कर आसन की इजाजत से बोलियेगा तब न आसन संज्ञान लेगा । सब आदमी वेल में आ गये, एक आदमी बोल रहे हैं, बाकी आदमी टेबल पकड़े हुये हैं । आसन सुनेगा, बताईये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सत्यदेव जी, आसन मानता है कि इस सदन के जो भी माननीय सदस्य जो भी मुद्दा उठाते हैं, सब महत्वपूर्ण और गंभीर होते हैं और महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दे को उठाने के लिये सदन की नियमावली में अलग-अलग प्रावधान किये गये हैं, जिसे आप समय से उठाईयेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अवधेश बाबू इतने पुराने लीडर हैं और ये कब से सदन में हैं और इनको नियमावली की जानकारी नहीं है? महोदय, कार्य-संचालन नियमावली में लिखा हुआ है कि किस समय कार्य-स्थगन सूचना आयेगा, किस समय निवेदन आयेगा, किस समय अल्प-सूचित प्रश्न आयेगा, किस समय तारांकित प्रश्न आयेगा । नियमावली को पढ़ करके भी, महोदय, ये भूल रहे हैं, इनके मम्बर का सवाल है, माननीय अमिता भूषण जी का सवाल है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि इनके सवाल का जवाब हो । सवाल का जवाब इनको लेना चाहिए, अगर आपने प्रश्न किया है तो ।

अध्यक्ष : माननीय अवधेश बाबू, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य आपकी वरीयता का हवाला देकर कह रहे हैं कि आपको अपनी सीट पर जाकर बोलना चाहिए । वेल में आकर नहीं बोलना चाहिए । वह आपके वरीयता से प्रभावित हैं ।

(व्यवधान जारी)

आसन किसी को समझाता नहीं है । इसलिये कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य खुद समझदार हैं । आसन किसी को नहीं समझा सकता है ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने सीट पर जाकर बोलियेगा न ? समय पर बोलियेगा, हम उसका संज्ञान लेंगे । अब तो अपनी सीट पर जाईये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय श्री महबूब आलम जी, आप जो प्ले कार्ड लिये हुये हैं, आप उसको गौर से पढ़े हैं ? उसमें क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिये । उसमें गलत लिखा हुआ है । आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं और खुद आपको पता नहीं है कि उसमें गलत लिखा हुआ है । आप पहले उसको पढ़िये । सामने लेकर पढ़िये कि क्या लिखा हुआ है । फिर आप पीछे पढ़ रहे हैं । इधर से घुमाईये और उसको पढ़िये ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने एक पत्र आदरणीय रामदेव बाबू के नाम लिखा है । उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मेरा प्रश्न, जो 26 फरवरी,20 को आ रहा है, प्रश्न संख्या-134 है, उसको पूछने के लिये उन्होंने अधिकृत किया है तो किस हैसियत से बिना विधायक दल के नेता की अनुमति के सदन को कांग्रेस के नेता बाधित कर रहे है, सदन यह जानना चाहता है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय महबूब जी, आप दूसरे के चेहरे से उसकी पढ़ाई मत कीजिये । आप खुद पढ़िये । हम तो पढ़कर ही आपसे कह रहे हैं । वह गलत लिखा हुआ है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सत्यदेव जी, आप अपने लीडर श्री महबूब आलम जी का क्वेश्चन तो ठीक करा दीजिये पहले । आज लगता है कि किसी दूसरे से लिखवाकर लाये हैं । लगता है आज ऑरीजिनल आदमी नहीं लिखा है । आज उसमें बहुत गलती है ।

चलिये, अब सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-2/राजेश/26.2.20

(व्यवधान)

अध्यक्ष: रोज अगर समाज के एक-एक हिस्से की मांग को लेकर प्रश्नकाल को बाधित कीजियेगा तो सदस्यों की मांग कब पूरी होगी ? इस सदन में भी सारे बिहार के प्रतिनिधि हैं, यह सदन भी किसी खास इलाके का नहीं है और अगर आपलोगों की यही इच्छा है कि माननीय सदस्यों के प्रश्न का जवाब नहीं हो पाये, तो आसन को मजबूर होना पड़ेगा, अब तो हम फिर से आग्रह करेंगे कि अपने स्थान पर जाइये और सदन की कार्यवाही को चलने दीजिये, आप ही का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: चलिये, अब सदन की कार्यवाही, एक बार फिर कहते हैं, चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री: महोदय, ये जो विषय उठा रहे हैं, इनको इस विषय में कोई रुचि नहीं है, यह केवल अपनी पार्टी के अंदरुनी झगड़े के कारण, इस आर0जे0डी0 में एक गुट है, जो सिद्दिकी साहब को पसंद नहीं करता है, तो सिद्दिकी साहब का प्रश्न न आ जाय, इसलिए आर0जे0डी0 के लोग हंगामा कर रहे हैं और ये जो कॉग्रेस के नेता हैं अमिता भूषण जी, ये बड़ी नेता बनती जा रही हैं, इसलिए अवधेश बाबू, अमिता भूषण जी का क्वेशचन नहीं आए, इसके लिए हंगामा ये लोग कर रहे हैं, इनको शिक्षकों से कोई रुचि नहीं है, ये लोग पार्टी की अंदरुनी झगड़े के कारण, ये लोग पार्टी के नेताओं के प्रश्न को नहीं आने देने के लिए केवल हंगामा कर रहे हैं, ये लोग अपनी पार्टी के झगड़े में हमलोगों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं महोदय ?

अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/26-2-20

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 के लिए निम्नलिखित माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री महबूब आलम, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नवाज आलम, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री शमीम अहमद। आज सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3)के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है।

अब शून्यकाल ।

(शून्यकाल)

(व्यवधान)

(इस बीच विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय,गंभीर मामला है शिक्षक हड़ताल पर हैं और शिक्षकों को सरकार अपना कर्मी मानती ही नहीं है।

अध्यक्ष: गंभीर मामले को उठाने के और भी तरीके हैं उठाईयेगा जिस पर सरकार भी कुछ कहने को मजबूर होगी । ऐसे ही अमान्य किये जाने पर बोलियेगा तो सरकार भी नोटिस नहीं ले पायेगी।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,अति महत्वपूर्ण विषय है और माननीय अध्यक्ष महोदय यह कोई एक जगह का मामला नहीं है, पूरे राज्य का मामला है। यह शिक्षकों की समस्या का मामला है। चार लाख शिक्षक इस राज्य के रोड पर हैं जिन पर लाठी चल रही है जिनको बर्खास्त किया जा रहा है जो धरने पर बैठे हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर हम जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है इस पर आपको चर्चा करानी चाहिए महोदय, ये हमारा व्यक्तिगत सदन और आसन से अपील है कि इन शिक्षकों के प्रति आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सदन में चर्चा करायें।

अध्यक्ष: ठीक है। अब शून्यकाल, श्री ललन पासवान।

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के भदौरा पंचायत के बांदु गांव स्थित सोन नदी में स्थित बाबा दशशिसा नाथ महादेव त्रेता युग से स्थापित है। सावन महीने में वहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने जाते हैं। सरकार से उक्त स्थल को पर्यटक स्थल में शामिल कराने हेतु मांग करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: श्री मो0 नावाज आलम।

अनुपस्थित

अध्यक्ष: श्रीमती पुनम देवी यादव।

श्रीमती पुनम देवी यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बी.एड. कोर्स के नियमित छात्र-छात्राओं को सत्र 2018-19 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन समर्पित करने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई कर छात्र छात्राओं को अविलम्ब छात्रवृत्ति दिलवाया जाय।

अध्यक्ष: श्री विनोद प्रसाद यादव।

आप लोग सीट पर जाईए आपलोगों का भी शून्यकाल सूचना है।

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय,गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी पंचायत एवं आसपास के इलाके के लोगों को ईलाज हेतु करीब 15 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है। कचौड़ी स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जनहित में अविलम्ब कचौड़ी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: श्री विजय कुमार खेमका।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय,पूर्णियां सहित राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में नगर विकास द्वारा बिजली पोल पर एल0ई0डी0 लाईट की सुविधा है परन्तु पंचायतों में यह सुविधा नहीं है। अत: सरकार से शहरी तर्ज पर पंचायतों में पंचायती राज विभाग से बिजली पोल पर एल0ई0डी0 लाईट लगाने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय,पूर्वीचम्पारण जिलान्तर्गत पिपरा विधान-सभा क्षेत्र के पिपरा में विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0भी0ए0 का शिलान्यास ऊर्जा मंत्री द्वारा दिनांक 14-12-2004 को हुआ था लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अत: पिपरा में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कराया जाय।

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ।

श्री समीर कुमार महासेठ:शिक्षक पर ही है लेकिन हाउस आर्डर में नहीं है, करें क्या?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: ठीक। श्री शमीम अहमद।

अनुपस्थित

अध्यक्ष: श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी।

अनुपस्थित

अध्यक्ष: श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय,उत्तर बिहार के पूर्वी चम्पारण जिला सहित अन्य जिलों में दिनांक 25-02-20 को भारी वर्षा तूफान एवं ओला गिरने से किसानों के फसल सहित जानमाल की काफी क्षति हुई है। क्षति का सही आकलन कराकर किसानों के फसल सहित जान माल बर्बादी हेतु उचित मुआवजा के लिए मांग करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य</u>

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचना । श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें। चलिये, नॉट मूव्ड ।

श्री शत्रुध्न तिवारी। आप ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री शत्रुध्न तिवारी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह एवं
अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर
<u>सरकार (पथ निर्माण विभाग/परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री शत्रुध्न तिवारी: अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी पर दीघा पहलेजा के बीच निर्मित जे0पी0 सेतु पर 12 चक्का, 16 चक्का वाले भारी वाहन क्षमता से अधिक भार लाद कर गुजर रहे हैं । दिनांक- 24.02.2020 को भारी वाहनों और बालू लदे ट्रकों की लम्बी कतार दिन में पुल पर लगने के कारण सारण जिला के नयागांव से दीघा तक घंटों जाम लग रहा जिसमें कई एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे । इस पुल की वर्तमान बनावट एवं क्षमता भारी वाहनों का भार सहने की नहीं है । भारी वाहनों के परिचालन से पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है । अत: दीघा के जे0पी0 सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन को रोकने और जाम की समस्या के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: 28 तारीख को इसका जवाब देंगे ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/मधुप-हेमंत/26.02.2020

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद अब प्रारंभ होगा और आज सरकार के उत्तर तक सदन की कार्यवाही अवधि रहेगी ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारे संशोधन को नियमानुकूल स्वीकार करने के लिए आसन को मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर बोलने का जो मौका आपने दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ ।

महोदय, सबसे पहले, आज जो देश की हालत है, आप देखिएगा कि जिस प्रकार से दिल्ली आज जल रहा है, इसकी हम निन्दा करते हैं । आज देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है । अभी हाल में हमलोगों ने दिल्ली चुनाव का परिणाम देखने का काम किया और यह भी दिल्ली के चुनाव में देखा है कि किस प्रकार से जहर बाँटने की राजनीति हो रही थी, खास तौर पर भाजपा के केन्द्रीय मंत्री द्वारा जिस प्रकार से उकसाने वाले बयान और नारे आये हैं, यह साफ बताता है कि अगर बी0जे0पी0 के लोग चुनाव हारेंगे तो वे शहरों को जलाने का काम करेंगे ।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए) (व्यवधान)

सबको अपनी बात बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?

(व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा तो आप अपनी बात बताइयेगा । चलिए, आप जारी रखिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है इसलिए इसको कार्यवाही से हटाया जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह देश महात्मा गाँधी, अम्बेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी का देश है और इस देश में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है । हमलोग अमन-चैन और गाँधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी के विचार...

अध्यक्ष : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्री के बारे में कहा है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह देश संविधान से चलने वाला देश है और यह साफ संदेश है देश के लोगों को, जो दिल्ली जल रहा है, कि अगर आप भाजपा को चुनाव हराओगे तो वे शहरों को जलाने का काम करेंगे, वे दंगा-फसाद करेंगे ।

आप देखिएगा, जिस प्रकार से इनके जो एलायंस पार्टनर हैं, जिस हिसाब से संविधान को या संवैधानिक इंस्टीच्यूशन्स को बर्बाद करने का काम किया है, चाहे आर0बी0आई0 हो, सी0बी0आई0 हो, ई0डी0 हो, इन्कम टैक्स हो, महोदय, यह सब लोगों ने देखा है और यह तो सबके सामने साबित हो चुका है कि किस हिसाब से ये लोग जितने भी संवैधानिक इंस्टीच्यूशन्स हैं, उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं । (व्यवधान)

महोदय, हमलोग काम की बात करें । जनता ने जनादेश आप सबको दिया है काम करने के लिए, विकास के लिए लेकिन बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का मतलब है कि विकास की यहाँ गंगा बहेगी और हमको नहीं लगता है कि बिहार में लगभग आप देखिएगा कि 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सत्ता में ज्यादातर उनके साथ भाजपा रही है, केन्द्र में उनकी सरकार छः साल हो गई, छठा साल, सातवाँ साल, जो भी चल रहा है और बिहार अभी भी गरीब है, अभी भी बिहार गरीब है । अगर बिहार 15 साल बाद भी डबल इंजन की सरकार में गरीब है, पिछड़ा है, और राज्यों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसका दोषी और कोई नहीं, केवल बिहार के मुख्यमंत्री और यह डबल इंजन की सरकार है ।

महोदय, बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं और हमलोग तो विपक्ष के लोग हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने हमको यह बोला कि आपको कुछ बातें हमपर नहीं बोलनी चाहिए थीं । देखिये, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम अभिभावक मानते हैं, सम्मानित हैं, सम्मान है, माननीय हैं, आदरणीय हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह पता होना चाहिए कि हम चाचा-भतीजे के हिसाब से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के नाते सवाल पूछने का काम करते हैं । महोदय, हम तो नेता विरोधी दल उन्हीं की कृपा से बने हैं और हमें सजा मिली कि नेता विरोधी

दल बना दिया गया । लेकिन हमारा गुनाह क्या था, यही गुनाह था कि हम तो बोलते थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, हमलोगों ने तो कई बार हर मंचों से कहा कि उनमें सारे गुण हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन आज जो भी, क्या हुआ, किस वजह से, डर है, लालच है, किस कारणवश वे गए, ठीक है लेकिन हमलोग तो अपना फर्ज निभायेंगे ही । जो जिम्मेदारी मिली है तो हम तो सवाल पूछेंगे ही । क्यों नहीं पूछेंगे सवाल ? क्यों नहीं हम पूछेंगे कि बिहार अबतक 15 साल आपके मुख्यमंत्री हुए हो गया बी0जे0पी0 के डबल इंजन की सरकार में, क्यों नहीं हमारा बिहार आगे बढ़ा ? क्यों नहीं हमारा बिहार तरक्की किया ? अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाँ हैं, महोदय । आप देखिएगा, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे, ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार किस हिसाब से पीछे है, यह कोई मेरा-आपका आंकड़ा नहीं है, बिहार की ही सरकार का है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, कोई हम अपने बगल से नहीं लाये हैं । बिहार का जो पर-कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है, वह 33,629 है, बिहार इकोनोमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है और जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जो आय है, वह 92,565 है । तो आप बताइये कि यह जो आंकड़ा है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 33 हजार, यानी तीन-गुणा राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय आगे है । हम क्यों पीछे हैं इस मामले में, महोदय । लगभग राष्ट्रीय स्तर से हमलोग तीन-गुणा कम हैं । आप देखिएगा, सिर्फ बिहार में ही अलग-अलग जिले हैं, जैसे कि शिवहर, पटना, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें लगभग नौ-गुणा का अन्तर है । जो डिस्पेरिटी है मतलब कि आप अलग-अलग देखिएगा कि कितना बड़ा डिस्पेरिटी विदिन बिहार के विभिन्न जिलों में भी है । पटना का जो है तो समझिए कि शिवहर के लोगों का प्रति व्यक्ति आय नौ-गुणा पीछे है । आखिर सरकार द्वारा इसमें सुधार करने के लिए, लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया गया, क्या योजना है, क्या दिशा है ? इसपर तो सरकार का कोई ध्यान नहीं गया 15 सालों में । आप देखिएगा... (व्यवधान) दूसरा आंकड़ा सुन लीजिए, जानना चाहिए, जानकारी होगी, 2004 में एक बिहारी पर कितना कर्ज था ? 5 हजार, एक व्यक्ति पर 5 हजार । आज 15 साल बाद आपके शासन के बाद हमारे एक बिहारी भाई पर 1 लाख 35 हजार का कर्ज है । यही विकास है ? यही डबल इंजन की सरकार है ? महोदय, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 1990 के दौर में, लालूजी के दौर में, आर0जे0डी0 के दौर में बजट साइज जो था, फलना हजार करोड़ का था, अब लाखों करोड़ का पहुँचा दिए । लेकिन महोदय, उनको यह भी साथ-साथ बताना चाहिए कि जो उदारीकरण 1990 के दौर से शुरू हुआ और जब

आप सत्ता में आए तब उसका लाभ उठाने का काम आप किए । यह बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताइये ।

अब बताइये, नीति आयोग का सर्वे रिपोर्ट आपलोग पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन आपलोगों को इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए... (व्यवधान) मेरा तो आयोग नहीं न है, आप ही लोगों का है, ठीक है, सबका है, तो जिस प्रकार से संवैधानिक इंस्टीच्यूशन्स आपलोग जो तबाह किए हुए हैं.... (व्यवधान) सबके बारे में आगे है । चलिए देश का है तो देश के आयोग में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, सबसे फिसड्डी राज्य है । (व्यवधान) महोदय, सतत विकास सूचकांक में बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य में सबसे फिसड्डी राज्य है । महोदय, नीति आयोग के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के सभी मानकों जैसे-बुनियादी सुविधाएँ, पुस्तकालय, कम्प्यूटर ऐडेड शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, परफौरमेंस आउट-कम इत्यादि में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, सबसे फिसड्डी राज्य है ।

...क्रमशः....

टर्न-5/आजाद/26.02.2020

..... क्रमशः .....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, शिक्षा का हाल हमलोगों ने देखा है, बिहार में कोई भी एक्जामिनेशन आप बता दीजिए आपकी सरकार में जहां पेपर लीक नहीं हुआ हो ? महोदय, बड़ा अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब जो है, छात्र-छात्रायें प्राथमिक विद्यालयों में अब ज्यादा जाने लगे हैं । बहुत अच्छा लगता है । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यह क्यों नहीं बताते कि दसवीं तक जाते-जाते ये बच्चे 56 फिसदी तक ड्रौपआऊट हो जाते हैं । ये आंकड़ा तो नहीं बताते हैं, पूरी बात जनता को बताना चाहिए, ये किस बात के लिए पीठ थप-थपा रहे हैं । क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता को तो पूरी तरीके से आपकी सरकार ने चौपट कर दिया है । कहीं शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षक अलग परेशान हैं और छात्र अलग जा रहे हैं । जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, लाठी-डंडे वाली सरकार उनपर लाठियां-डंडे बरसाने का काम कर रही है । सरकार के गलतियों को सुधारने के लिए, धरना-प्रदर्शन यह सबों का लोकतांत्रिक अधिकार है, यदि कोई त्रुटियां हुई हैं तो देखिए इसको एकसेप्ट कर लेना चाहिए । अगर एकसेप्ट नहीं करोगो तो बिहार और पीछे चला जायेगा । गलती को मानिए, सुधारिये और उसपर काम

कीजिए । आपलोग उस गलती को न मानते हो, न सुधारते हो, दे दना-दना, दे दना-दना गलती पर गलती ठोकते जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं ?

महोदय, आप देखिए जो हमारा कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन दु:ख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि .....

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : ये यह भी बता दें कि चरवाहा विद्यालय का क्या हाल हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाईए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । इन लोगों का काम की बात भी पसन्द नहीं है और सच भी इन लोगों को पसन्द नहीं है, क्या करें, होता ही है दिक्कत । महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में । सिंचाई के बिना बिहार का अभी भी एक बड़ा भू-भाग कृषि योग्य नहीं है । आज देखियेगा लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई की उचित व्यवस्था के अभाव में गैर-कृषि योग्य बनी हुई है । 15 वर्षों में आप लोगों ने कौन सा कार्य इस क्षेत्र में किया है,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाईए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार के नगर निकाय वाले 143 शहरों में पाईप लाईनों से जलापूर्ति की स्थिति बहुत खराब है । बिहार के महज 17.6 फिसदी नगर निकायों के क्षेत्रों के घर में पेयजल की आपूर्ति होती है । कितना पेयजल की आपूर्ति होती है महोदय, शहरों की बात कर रहे हैं नगर निकायों की, मात्र 143 में से टोटल अगर निकाला जाय तो 17.6 फिसदी नगर निकायों के क्षेत्रों के घरों में पेयजल की आपूर्ति होती है । यह मेरा नहीं, आपके सरकार का ही आंकड़ा है, जो इकोनॉमी सर्वे किया गया है .....

अध्यक्ष : आप बोलिए न, क्यों उनकी बात सुन रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार का क्या विकास हुआ, शहरीकरण एवं शहरी विकास में बिहार आज भी सबसे पीछे क्यों हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना जवाब दें तो इसपर हमलोग जानना चाहेंगे कि क्यों इतना लाखों हेक्टेयर जो जमीन है, जिसकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उस जमीन पर कृषि नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे । हमलोग गुणवत्ता की भी बात करेंगे शिक्षा में, चिकित्सा में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा । कुपोषण सूचकांक में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें भी हम अंतिम स्थान पर हैं, बिहार जो है अंतिम स्थान पर है । यह हमलोगों का तो सर्वे नहीं है, यह तो आपलोगों का ही जो सरकार का सर्वे आते रहता है, आयोगा, सोशल इकोनॉमी का जो आते रहता है, वही है । महोदय, नीति आयोग के

रिपोर्ट में यह भी है कि एस0सी0, एस0टी0 के भाईयों पर सबसे ज्यादा अत्याचार बिहार में ही हुए हैं, यह रिपोर्ट में है । महोदय, पेपर लीक की बात हो जाय, क्राईम में तो बिहार को अव्वल नम्बर मिला है, क्राईम के क्षेत्र में बिहार को अव्वल नम्बर मिला है । मुख्यमंत्री जी के पास होम मिनिस्टरी है, उनको बताना चाहिए बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, बहन-बेटियां जो असुरक्षा की भावना उनके मन में पैदा हुई है, कितना घिनौना काम बालगृह में हुआ, कितना घिनौना काम हुआ, इससे हमलोगों का सर झुक जाता है । कौन बच्चियों के साथ हुआ था, वही बच्चियां जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है, इनके लिए होम सेन्टर बनाया गया था, वो तो लड़ाई हमलोगों ने लड़ी लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस बच्ची ने उजागर किया, उस बच्ची के साथ दोबारा गैंग-रेप होता है सीतामढ़ी में । सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, पता नहीं आपलोग सुनते होंगे, डेली फटकार लगता था, जब डेट होता था बालिकागृह के मामले में, ये लोग तो महोदय सी0बी0आई0 को जॉच के लिए नहीं दे रहे थे, अगर हमलोग जंतर-मंतर तक धरना नहीं देते तो सी0बी0आई0 जॉच ही नहीं होता और गुनाहगार को सजा ही नहीं मिलता महोदय तो आप देखिए बिहार में किस हिसाब से अपराध जो है, चरमसीमा पर है । इसपर हमलोगों को टिका-टिप्पणी ज्यादा नहीं करना है, यह सबके सामने है लेकिन अभी भी मूँछ वाले और तौंद वाले अंकल बचे हुए हैं । वो अभी भी अधिकारी से लेकर बहुत लोग हैं, हमलोग इसके लिए उच्च अदालत जायेंगे । समय पर हमलोग जायेंगे, सबूत पेश करेंगे और बच्चियों के साथ जिन लोगों ने घिनौना काम किया है, उनको हमलोग बख्सने का काम नहीं करेंगे । महोदय, लगातार बेरोजगारी, 10 मिनट महोदय .....

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलने दीजिए, तेजस्वी जी आप बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप किस पार्टी की है, आप बी0जे0पी0 की है, हमें ज्यादा मत बोलवाईए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जाईए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : मंत्री नहीं बनियेगा, बैठ जाईए । महोदय, बेरोजगारी, देश जो है विश्व में सबसे युवा देश है हमारा और बिहार जो है, देश में सबसे युवा प्रदेश है । बिहार में 7 करोड़ नौजवान हैं, 7 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इस सरकार ने क्या किया, केवल लाठी और डंडे बरसाने का काम किया है । महोदय, एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट में हाईस्ट इमप्लायमेंट है 45 साल बाद, यानी हाईस्ट

इमप्लायमेंट है 45 साल बाद, एन0एस0एस0ओ0 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के सिर्फ 12 फिसदी लोग ही नौकरी करते हैं जो देश के प्रमुख 18 राज्यों में से सबसे कम हैं । महोदय, सबसे ज्यादा युवा प्रदेश हमारा और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है । हमलोग युवा हैं और हमलोगों की चिन्ता होती है कि बिहार जो है बेरोजगारी का केन्द्र क्यों बना हुआ है, कभी तो गंभीर हो जाईए भईया, गंभीर विषय पर बात हो रही है । आप 7 करोड़ बेरोजगारों के साथ भेद-भाव कर रहे हैं, आप 7 करोड़ नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं,

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए । बैठ जाईए न ।

(व्यवधान)

टर्न-6/शंभु/26.02.20

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : 15 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार ने कितने रोजगार सृजन किये, कितने युवाओं को नौकरी दिया, कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालय जाकर के पंजीकरण कराया, रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के लिए सरकार के पास कोई अल्पकालिक उपाय नहीं है और न ही कोई दीर्घकालिक नीति या दिशा है, यह हम सदन में बताना चाहते हैं । महोदय, 7 करोड़ युवा आबादी को भगवान भरोसे नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया है । बिहार के पास अधिकतम मानव संसाधन है इसके बावजूद सरकार के पास उनका राज्य के विकास में उपयुक्तता का लाभ उठाने की कोई नीति या दिशा नहीं है । हमारे मानव संसाधन से दूसरे राज्य तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में बिहार अपने ही मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा है । महोदय, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई भी कर रहा है । महोदय, एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि सदन में इसकी बात होनी चाहिए और सदन को पता भी चलना चाहिए- बार-बार लोग कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल । आप बताइये कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला ? डबल इंजन की सरकार में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया ? महोदय, जब लालू जी सेंट्रल में थे, राष्ट्रीय जनता दल सेंट्रल गवर्नमेंट में थी और वे रेल मंत्री बने पहला यू0पी0ए0 में उसमें बिहार को 1 लाख 44 हजार करोड़ रूपये दिया गया । हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस डबल इंजन की सरकार में कितना मिला ? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें सबसे ज्यादा और राज्यों के मुकाबले बिहार को दिया गया । उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह जी केन्द्रीय

ग्रामीण विकास मंत्री थे । मिड-डे मील जैसी स्कीम । नेशनल हाइवे आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस गाड़ी से उतरकर भाग जा रहे हैं । वे कह रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है और पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि नेशनल हाइवे में बिहार को कितना पैसा मिल रहा है । हमलोग जब थे तो कितना कुछ काम करवाये थे, उसमें मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, चूंकि सारा आंकड़ा इनके पास होगाा, लेकिन अब बतायें न कि डबल इंजन की सरकार में नेशनल हाइवे में कितना पैसा मिल रहा है ? कोशी बाढ़ में जब लालू जी थे, जब 2007-08 में आया था तो 5 जिलों में 1100 करोड़ रूपया दिया । आपके डबल इंजन की सरकार ने कितना बाढ़ पीड़ितों को दिया? हम जानते हैं मुख्यमंत्री जी की चिंता, परेशानी- क्या मिला बिहार को ? कितनी बार बोलने के बाद भी सर्वे करने लोग नहीं आता था, आज सर्वे आकर के सर्वे करके चला भी जाता है तो क्या होता है ? बिहार को ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है । बी0जी0आर0एफ0 पर- जो आज लाभ उठाया जाता है बी0जी0आर0एफ0 फन्ड का । बी0जी0आर0एफ0 बोर्ड का गठन कब हुआ था और उस समय बी0जी0आर0एफ0 बोर्ड का गठन करवाया लालू जी की सरकार ने और बिहार के सभी जिले को पिछड़ा घोषित करवाया था तब जाकर के बिहार में जो थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा वह आपलोगों को दिखने का काम करता था । नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक....

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : नेता प्रतिपक्ष एक मिनट सुन लीजिए आप ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे.....

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : आप बी0जी0आर0एफ0 बोल रहे हैं, बी0आर0जी0एफ0 बोलिये ना, अरे आप गलत बोल रहे हैं । मैं केवल इनको करेक्ट कर रहा हूँ ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ठीक है बी0आर0जी0एफ0 । आपको जानकारी है न कि कब हुआ बोर्ड का गठन ? कब हुआ यू0पी0ए0 के समय हुआ ।

(व्यवधान)

बैकवर्ड रीजन ग्रांट फन्ड ठीक है बैठ जाइये, हम फुलफोर्म बता दिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इधर मुखातिभ होकर बोलिये । अब आपके पास 3-4 मिनट समय है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, जाइका जैसे राज्य सरकार को लोन देने की अनुमति दिलवायी गयी । पहले राज्य सरकारों को जाइका से, वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से लोन लेने की अनुमति नहीं थी महोदय । रेलवे के कारखाने खोले गये थे महोदय, गरीब रथ जैसे ट्रेन, गरीब भी ए0सी0 में चले । उसका लाभ लोगों ने उठाने का काम किया, गरीबों ने उठाने का काम किया, लेकिन अब सब

गरीब रथ को बंद किया जा रहा है । 90 हजार करोड़ का लालू जी ने मुनाफा देने का काम किया, लाखों को रोजगार दिया और आर0ओ0बी0 जितना बनता था उसमें पूरा सेंट परसेंट रेलवे दिया करती थी, लेकिन इस सरकार ने कितना देने का काम किया । आपलोग बात करते हैं बिहार की- जब बिहार लालू जी के हाथ में आया था 90 के दशक में तब गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन गिरवी था बता देते हैं और जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार को 37 करोड़ मुनाफा देने का काम किया और 2500 करोड़ लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार नुकसान में था, गिरवी रखा हुआ था । ये चीजें क्यों नहीं बतायी जाती है महोदय । आप हर बार लालू जी को दोष ठहराना बंद कीजिए और अपनी दिशा के बारे में बताने का काम कीजिए ।

(व्यवधान)

पहले इस बात से तो सब सहमत होइये कि अफसरशाही है, इस सरकार में अफसरशाही है, विधायक की तो छोड़िए मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है । अफसरशाही गरीब जनता की तो छोड़िए, पार्टी के पौलिटिकल वर्कर की छोड़िए । इस बात से सब सहमत होंगे कोई अधिकारी सुनता है ? कोई अधिकारी नहीं सुनता है । महोदय, इस सरकार में किसी जनप्रतिनिधि की पूछ नहीं होती है, कोई पूछ नहीं होती है । लालू जी के समय एक गरीब को भी डी0एम0 औफिस में बैठाकर चाय पिलाया जाता था मान सम्मान के साथ उसकी समस्या सुनी जाती थी, उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाता था । वह गरीब का राज्य था, यहां तो लगता है कि 3-4 अफसर हैं वही बिहार को चला रहे हैं । पटना युनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा कब मिला, नहीं मिला ये तो यही बतायेंगे । महोदय, हालांकि कोई काम की बात बी0जे0पी0 के लोगों को सुनने की आदत नहीं है उनको खाली दंगा-फसाद, मार-काट ये लोग नाथूराम गोडसे के वंशज हैं । ये लोग काम में, विकास में विश्वास ही नहीं रखते हैं । ये लोग गांधी जी के हत्यारे हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को भद्दी-भद्दी गालियां देने का काम किया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे ये बोल ही रहे हैं तो आप काहे के लिए बोल रहे हैं, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये । चलिए अब बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, 2 मिनट में हम कन्क्लुड करते हैं ।

अध्यक्ष : अब कन्क्लुड कर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सम्मानित मंत्री जी बैठ जाइये । महोदय, अब हमलोगों को गाली नहीं देते तो मंत्री कैसे बनते ? लालू जी को गाली नहीं देते तो मंत्री कैसे बनते ? हम लोगों को गाली नहीं देंगे तो रोजगार इनका कैसे चलेगा ? चलो कोई तो रोजगार सृजन हुआ । बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे बात बिगाड़ने का काम मत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, और भी जो लिखित में है हम चाहेंगे बिहार में डबल इंजन की सरकार यानी यह स्पष्ट है कि बिहार में 55 बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं कोई बड़ा अधिकारी, मंत्री जेल नहीं गया - धान घोटला, बियाडा घोटला, बांध घोटाला से लेकर सृजन घोटाला तक के अपराधी बाहर घूम रहे हैं, जॉच का अतापता नहीं हमको सब खेल पता है । महोदय, 55 घोटाले हुए यानी साफ स्पष्ट है कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन अपराध में है । और ज्यादा कुछ हम न कहते हुए ये लोग गंभीर नहीं है, ये लोग थके हुए हैं थक गये हैं । अब बिहार इन लोगों से नहीं चलनेवाला है और जनता मन बना ली है । जनता ने मन बना लिया है चिंता मत कीजिए । महोदय, हम आसन से चाहेंगे कि हमारा और जो लिखित भाषण है उसको सबमिट करते हैं । इसको इन्क्लुड कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द ।

परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य ।

टर्न-7/26-02-2020/ज्योति-मुकुल

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ? अभी तो नेता प्रतिपक्ष ने बोलना खत्म किया, इस पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मुख्यमंत्री जी, बैठे हैं । अमर्यादित लोग को इन्होंने मंत्री बना दिया और यह बिहार के लिए कलंक है न हुजूर ? इनको बर्खास्त करना चाहिए ।

अध्यक्ष : अब दूसरे मंत्री जी का सुनिये ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने बड़े जोशो-खरोशो के साथ भाषण दिया, लेकिन महोदय इनके बयान में इतनी गलत-बयानी थी कि इनके पार्टी के आधा भी विधायक उपस्थित नहीं हो पाए

इनका भाषण सुनने के लिए । यह बताता हैं कि इनकी बातों में कोई दम नहीं था, केवल हवा-हवाई बात थी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है ..

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र जी, आपका समय 5 ही मिनट है इसी परिप्रेक्ष्य में बोलियेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : जी महोदय । मैं कहना चाहता हूँ सदन को कि यह बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है । ये बिहार, ये जो बिहार चाणक्य का बिहार है, गौतम का बिहार है, गर्ग का बिहार है, जिस बिहार की तुलना जब पिछले के 15 वर्षों के राजकाल से जो एक परिवार का राज था और वैसे लोग जब इस बात की चर्चाएं करते हैं तो मुझे भी दुख होता है और इस सदन को दुख होता है। मैं कुछ पहलुओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बिहार सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ रहा है । अभी आदरणीय विरोधी दल के नेता बोल रहे थे कि लालू जी ने इतने रुपये का रेल में मुनाफा दिखाया, शायद ये बात भूल गये हैं कि ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, लालू जी के बाद तो ममता बनर्जी ने लालू जी के खिलाफ में श्वेत-पत्र जारी किया था और कहा था कि जिन पैसों की बढ़ोतरी उन्होंने बताया है, वह सरासर गलत है, नाजायज है । महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, जिस शिक्षा की बात कर रहे थे, 15 वर्षों में बी.पी.एस.सी. ने मात्र 8 परीक्षाओं को कंडक्ट किया था बिहार में और नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के राज में 15 वर्षों में उसी बी.पी.एस.सी. ने 23 परीक्षाओं को कंडक्ट किया इसी बिहार में। अब ये तुलना कर सकते हैं कि जो 15 वर्षों का एक परिवार पति-पत्नी का राज था और जो 15 वर्ष नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी का राज है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। जिस सरकार में अंधेरों में लोग चलते थे, आज सभी गरीबों के घर में, बिहार में बिजलियां जल रही हैं और आज यह राज-साठ खराब लग रहा है। ये चाहते हैं कि उसी लालटेन का युग आवे, बिजलियां समाप्त हों, लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे महोदय, बिहार में इस चीज की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जिस कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे, मुझे याद है और इस सदन को याद होगा कि 15 वर्षों के समय काल-खंड में तिसमारा, तिसकोरा, लक्ष्मणपुर, बाथे, शंकरबिगहा जैसे नरसंहार हुए, जिसमें पचासों-सैकड़ों लोग काट दिए गए खड़ा कराके अपने-अपने घरों में, आज कोई

नरसंहार 15 वर्षों में बता दें इस सदन का कोई भी सदस्य कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी के राज्य में कोई नरसंहार हुआ है, लेकिन उस 15 वर्षों के राज्य में सैकड़ों नरसंहार का उदाहरण दे सकता हूँ माननीय महोदय और आपको भी याद होगा कि सैकड़ों-सैकड़ों लोग काट दिए गए अपने-अपने घरों में जला दिए गए और कानून की बात आप कर रहे हैं । बिहार सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास कर रहा है चाहे बिजली का क्षेत्र हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का कौशल विकास के माध्यम से काम हो या इस सरकार का कोई भी काम जो बिहार के हित में जरूरी है आज बिहार एक विकसित बिहार, बिहार एक रौल मौड्ल बन रहा है पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बन रहा है। बिहार के सदन में बैठकर और दिल्ली की बातें की जाती हैं कि देश में यह हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हुआ 15 वर्षों तक और आगे के 14 वर्षों में क्या हुआ, इसकी चर्चाएं नहीं की जाती हैं । महोदय, आपने मुझे समय कम दिया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कुछ विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । कल का महोदय, जो दिन था कल का दिन बिहार के लिए एक अपशगुन का दिन था, पूर्वी चम्पारण कल्याणपुर विधान सभा सहित पूरे उत्तर बिहार में भारी ओला-वृष्टि हुई है, भारी वर्षा हुई, काफी आंधियॉ आयी हैं, सैकड़ों घर गिर गए हैं, पेड़ उजड़ गये है, कई लोग उसमें मर भी गए हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर ले जाना चाहता हूँ जिस समस्या से उत्तर बिहार का कई इलाका, कई गांव, कई शहर और कई जिला प्रभावित है, उसके लिए एक समुचित व्यवस्था बनाकर उसके लिए आप जो मुआवजा की व्यवस्था है शीघ्र आप उस मुआवजा को देने का काम करेंगे। महोदय, मैं कुछ और समस्याओं की तरफ इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं खासकर शराब के मामले में कहना चाहूंगा, मैं मांग करता हूँ कि अपने राज्य से लगी हुई जितनी सीमाएं हैं, दूसरे राज्य से आने वाली जितनी सीमाएं हैं या दूसरे देश से लगी हुई सीमाएं सभी सीमाओं पर एक्सरे स्कैनर मशीन लगाए जाने की आवश्यकता है । इसलिए कि जिन गाड़ियों से अवैध शराब अपने राज्य में लायी जाती है शायद उसका ठीक से स्कैनिंग नहीं होता है अगर एक्सरे स्कैनर मशीन लग जाती हे तो वैसी समस्याओं को रोकने में इस सरकार को भी और यहॉ भी लोगों को सुविधा प्राप्त होगी । महोदय, कुछ और विषयों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आपके माध्यम से गन्ना किसान जो उत्तर बिहार के एक बड़े इलाक में गन्ने की बुआई होती है और गन्ने की फसल ज्यादा होती है वैसे गन्ना किसानों का आज के

दिन में करोड़ो रुपया गन्ना मिल-मालिकों के जिम्मे बाकी है चाहे वह सासामुसा फैक्ट्री का मामला हो, रीगा फैक्ट्री का मामला हो या गोपालगंज के अन्य फैक्ट्रियों का मामला हो करोड़ो रुपये गन्ना किसानों का चीनी मिलों के जिम्मे बकाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गन्ना किसानों के जो बकाया है, उस पैसे को गन्ना किसानों को पेमेंट दिया जाना चाहिए ताकि उन किसानों को ससमय उसका लाभ प्राप्त हो सके और उससे अपनी खेती-बाड़ी को आगे बढ़ा सके महोदय, एक से एक काम इस बिहार में हो रहा है । कोई बड़ा घोटाला उस प्रकार का नहीं हुआ आज तक बिहार में और जो बोल रहे थे मुझको लगता है कि जो बोल रहे थे, उनके गार्जियन शायद सत्याग्रह के आन्दोलन में जेल में बंद हैं । सत्याग्रह के आन्दोलन में बंद नहीं हैं किसी न किसी घोटाले में बंद हैं, जिसको पूरा बिहार नहीं पूरी दुनिया जानती है। महोदय, ऐसे लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैंने अपनी बात रखी । मैं आपके प्रति और अपने कल्याणपुर विधान सभा की महान जनता के प्रति जिस जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, मैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए और पूरे सदन के प्रति पूरे सदन ने मेरी बात को सुना बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री सुदामा प्रसाद जी । आप 5 मिनट में बिना मेरे द्वारा स्मारित किये गये बैठ जाइये।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आपका आभार आपने बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो हड़ताली शिक्षक हैं, उनके न्यायोचित मांग पर ध्यान दिया जाय । दमन का सहारा बंद किया जाय, वह भी हमारे समाज का हिस्सा है, वे देश का भविष्य तैयार करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वह बिहार की जमीनी सच्चाई से परे है । महोदय, सरकार ने शराबबंदी कानून लाया था और शराबबंदी के लिए अभियान चला था, मानव श्रृंखला भी बनी थी, लेकिन इतने महत्वपूर्ण सवाल पर एक शब्द नहीं कहा गया है। महामहिम के अभिभाषण में यह सीधा-सीधा यह कानून गरीबों के खिलाफ में है । एक भी शराब माफिया अगर जेल भेजा गया हो तो आप बताए सरकार पचास करोड़ रुपये की शराब पकड़ी गयी हाजीपुर में । ट्रक के खलासी ड्राईवर को पकड़ कर जेल भेज दिया गया लेकिन उसका मालिक ? मालिक कहाँ गया एक भी शराब माफिया जेल नहीं गया, लेकिन बिहार के विभिन्न जेलों में 1 लाख 29 हजार गरीबों को बंद कर दिया गया कि ये शराब पिए हुए थे तो ये तो गरीबों के खिलाफ में है, शराब माफियाओं के पक्ष में है। क्या शराब बंद है ? हर रोज थाना में एस.पी. को छापामारी करना पड़ रहा है और 149 बोतल शराब पकड़ी गयी । क्या शराब

बंद है ? नहीं चल रहा है, गरीबों के खिलाफ में यह कानून है इसलिए हम कहेंगे कि तमाम गरीबों को बाईज्जत बरी किया जाय और सरकार इस ढंग का कानून लाए। दूसरी बात कहेंगे कि यहॉ खूब धूम-धड़ाका होता है योजना का- जल जीवन हरियाली चल रही है ।

क्रमशः

टर्न-08/कृष्ण/26.02.2020

श्री सुदामा प्रसाद क्रमश : साढ़े महीने के बाद मैं समझता हूं उस पर ध्यान देने की जरूरत है । 13 जुलाई को फिल्म दिखाई गयी थी, कांवर झील के बारे में साढ़े 12 हजार एकड़ कांवर झील का भूमि माफियाओं ने दखल किया है । महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या एक भी भूमि माफिया के पास सरकार ने नोटीस भेजा, नहीं भेजा । लेकिन बिहार के लाखों लोगों को नोटीस भेज दिया गया । पश्चिम चम्पारण में दो गांवों में गरीबों का मकान ढाह दिया गया एकडरी पोखर में और सुखीडीह पोखर में । सेदहां में ढाह दिया 18 घर तो यह सरकार किस के लिये कार्य कर रही है ? योजना चलती है गरीबों के नाम पर और हर योजना का गाज गरीबों पर ही गिरता है । हर घर नल के जल में हजारों करोड़ खर्च हो गया लेकिन उपलब्धि क्या है ? उपलब्धि यह है कि गांवों की गलियों को कोड़ कर छोड़ दिया गया लेकिन 80 प्रतिशत से भी ज्यादा गांवों में पानी नहीं चल रहा है ।

महोदय, कृषि रोड मैप की बात कही गयी है । लेकिन बिहार का 80 प्रतिशत खेती बटाईदार किसान करता है कृषि का लेकिन सरकार ने आज तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया । उनको पहचान पत्र नहीं दिया । इसलिए उनको खेती की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है ।

महोदय, चौथी बात मैं भूमि सुधार के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पर्चा दिया, पश्चिम चम्पारण के मैनाटांड़ ब्लौक में बेलवा गांव में सीलिंग का पर्चा मिला, वहां के डी0एम0 ने भी 2013 में कहा था कि यह सीलिंग की जमीन है और बार-बार हमला करके जो खेती हुई, उसमें धान का फसल लगा हुआ था, गेहूं का फसल लगा हुआ है, हर साल बेलवा में हमला करके हरी फसलों को नष्ट कर दिया जाता है । तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ।

सरकार ध्यान दें । मान लीजिये कि सरकार यहां से पानी गया ले जायेगी, समुद्र तल से पटना की ऊंचाई 53 मीटर है और गया की ऊंचाई 111 मीटर, औरी का पानी बरेड़ी पर ले जाया जायेगा । लेकिन हमलोग लंबे समय से मांग करते आ रहे है कि मात्र 10 हजार करोड़ रूपया में सोन पदी में इन्द्रपुरी

जलाशय बन जायेगा तो मध्य बिहार में कहीं सूखा नहीं पड़ेगा और गया जिला में नालंदा जिला में इससे पानी ले जाने की व्यवस्था हो सकती है । तो सरकार को जो ठोस उपलब्धि वाली योजनायें है उस पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की जरूरत है । मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करूंगा कि हड़ताली शिक्षकों से बातचीत करे, उनका दमन बंद करे और उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री रामदेव राय जी । आपका समय है 8 मिनट लेकिन आप मिनट तक बोल सकते हैं ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, नेता, विपक्ष ने जितने सारे तर्क और तथ्य सदन के सामने रखें हैं, उन पर गहराई से सोचने की जरूरत है । मगर सदन तो हमेशा हलचल में ही रहता है । लगता है कि गहराई से सोचने की बात बहुत दूर रहती है और हमलोग चिंतित बैठे रहते हैं । न तो सरकार का ध्यान इधर है और न किसी मेम्बरान का । शायद 5वां वर्ष बीत रहा है, हमलोगों का समय निरर्थक बीतता चलाजा रहा है । हमलोग महत्वपूर्ण सवालों पर कोई काम नहीं कर पाते हैं । सरकार स्वयं चाहती है कि 50 वर्ष जिस तरह बिताये, उसी तरह 5 वां वर्ष बीता दें। महोदय, इस संबंध में मुझ को कुछ नहीं कहना है । आप 10 मिनट समय दिये, बड़ी कृपा किये ।

महोदय, जो बजट पेश किया गया और जो बजट भाषण किये हैं हमारे महामहिम जी, यह बजट भाषण उनका है । बजट भाषण के बारे में मैं एक बार और कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि आपत्तिजनक बात बोलूं, वे तो लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं, सरकार जो लिखकर देती है, वही पढ़ देते हैं । लेकिन चाहिये यह कि जो भी भाषण सरकार लिखकर दे, उसकी एक-एक पंक्ति को वे पढ़े और उसका अनुश्रवण जरूर किया करें, स्वयं न करें, उनके पास जो स्टाफ हैं, वह करें। ताकि बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने सच्चाई आवें । महोदय, इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जीरो टॉलरेंस की बात कही गयी है, बहुत दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी हमलोगों को यहां शपथ ग्रहण कराते हैं तो हमलोग ईश्वर का शपथ लेते हैं । वह कहते हैं कि लाईन में खड़े हो जाओ, हम स्टैंड अप हो जाते हैं । जब-जब खड़ा होने के लिये कहते हैं, हमलोग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं । हमलोग उनके सारे आदेशों का पालन करते हैं । मगर मैं जानता हूं, हमलोग उनके प्रतिनिधि हैं, वे भले नहीं समझें लेकिन हाउस के जितने मेम्बर हैं, उनके प्रतिनिधि हैं । लालू जी और इनकी सरकार में यही फर्क है कि वे अपने मेम्बरान के प्रति बड़ी मुखातिब रहते थे और यहां दुख यह है कि हम मुखातिब

नहीं रह पाते हैं । अगर मुखातिब रहते तो मैं बताता हूं सर, मैं चाहता नहीं हूं, एक बार मैं भोगा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी है, इसलिए मैं साहस करके कह रहा हूं । मैं स्वयं अपने प्रखंड में करोड़ों रूपये टेबुल पर पसरे हुये पखाना समन्वयक के द्वारा वसूल किया गया रूपया पकड़ा गया, बी0डी0ओ0 और एस0डीओ0 साहब स्वयं इसकी जांच किये, जांच करके रिपोर्ट किये, थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद समन्वयक साहब भाग गये, अभी तक पकड़ में नहीं हैं, सुनते हैं कि विभाग की कृपा से समस्तीपुर में फिर से ज्वाईन कर के काम कर रहे हैं । यह रिपोर्ट हळ । हम माननीय मुख्यमंत्री को सूचना देना चाहते हैं । आप यह कागज को देख लीजिये, अगर इसमें सच्चाई नहीं हो तो मैं गलत हो जाउंगा, अगर सच्चाई है तो आपके रहते, जीरो टॉलरेंस की सरकार रहते हुये, नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता इसके प्रति है, उसके रहते हुये इतना बड़ा घोटाला एक ब्लौक में हो रहा है तो बिहार की क्या हालत होगी, इस पर जायजा लेने की जरूरत है । हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं । आप नालंदा में भले ही ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिये हों लेकिन ओ0डी0एफ0 कहां घोषित हुआ, किसी एक ब्लॉक का नाम लीजिये, मंत्री जी स्वयं चले, जिसको इच्छा हो, उनको ले चलें । कहीं ओ0डी0एफ0 घोषित नहीं है । सिर्फ कागज पर है । हम मुख्य मंत्री के डर से ओ0डी0एफ0 घोषित करने के लिये चले गये । कहीं मुख्यमंत्री जी बिगड़ नहीं जाय। हमको कहा कि आप सब हाथ उठाईये, आ0डी0एफ0 मेरा ब्लौक घोषित, कह दिये कि मोदी जी बिगड़ जायेंगे, मुख्यमंत्री जी बिगड़ जायेंगे, श्रवण बाबू बिगड़ जायेंगे । हुजूर, चल कर जरा देख लीजिये, वह बेचारी गरीब महिला, जिसके लिये आप इतना काम करते हैं, वह आज भी खुले मैदान में शौच के लिये जाती है । उसके पास एक लौटा पानी भी नहीं रहता है । इससे दुखद हमारे लिये क्या हो सकता है ? हम कुछ नहीं बातना चाहते हैं, हम वही बताना चाहते हैं जो आपके लिये उचित है । आप पिछला वोट लोक सभा में गैस पर, पैखाना पर कुछ-कुछ प्रचार करके वोट जीते लिये, फटाफटा मार दिये लेकिन जानते नहीं कि अब चटाचट मारनेवाला भी समय आ गया है । आपका फटाफट दूर हो जायेगा और चटाचट जीत जायेगा फट से । देख लीजियेगा ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । हमलोग ऐक्टिव है । हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना और वह सफल नहीं हो, जितना आप नहीं खटते हैं, उनता मैं खटता हूं मुख्यमंत्री के लिये । मैं निश्चित रूप से उनके कुछ कार्यक्रम को स्वीकार करता हूं । लेकिन एक बात बोलिये आप । इसमें से कितने मंत्री हैं ? नन्द किशोरबाबू ।

अध्यक्ष : आप नन्द किशोर जी में मत उलझिये । आपका समय खत्म हो जायेगा ।

श्री रामदेव राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मंत्री शराब माफिया को रात के 12 बजे लाठी लेकर दौड़कर पकड़े और पुलिस के हवाले किये ? मैं संभव करके दिखा दिया हूं । यह यादव संभव करके दिखा दिया है । तीन-तीन बड़े माफिया को रात के 12 बजे, जिसके हाथ में बंदुक और पिस्तौल था, को पकड़ करके इसलिये दिया हिक मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलायी थी । बोलिये मैं प्रतिबद्ध हूं उनके प्रति या वे प्रतिबद्ध है हमलोगों के प्रति । हम प्रतिबद्ध है उनके प्रति । माफिया को पकड़ कर दिया और क्या हालत है ? ठीक डी0जी0पी0 साहब ने कहा है ।

क्रमशः

टर्न-9/राजेश/26.2.20

श्री रामदेव राय, क्रमशः सरकार शराब का कारोबार कराता है, मुख्यमंत्री जी अगर समय दें, तो मैं इतना हुलिया दूंगा उनको सबूत के साथ कि वे अचंभित रह जायेंगे, यह हालत है आपकी, अब मैं बजट पर बोलू की समस्या पर बोलूं .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब तो समय ही खतम है, तो अब कहॉ बोलना है ?

श्री रामदेव रायः हुजूर, इतना ही नहीं ।

अध्यक्षः अब खतम है समय ।

श्री रामदेव रायः हुजूर, यह देखिये, यह फोटो निकला है, यह फोटो किसका है,हम जान नहीं पाये हैं, यह प्रभात खबर है,अब बोलिये, कहीं आदमी का, कहीं मिनिस्टर का फोटो ऐसा होता है जानवर जैसा, देखिये तो, इसमें क्या लिखा है,इसमें लिखा है कि शिक्षित बिहार समृद्ध गॉव, 90 प्रतिशत लोग गॉवों में रहते हैं, 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, तीन बार रोडमैप बनाये आप लेकिन रोडमैप का क्या असर हुआ, मात्र 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अभी तक तीन रोडमैप पर, तब हम क्यों न माने .....(व्यवधान)

आपको बुझने ही नहीं आता है, तो हम क्या करें ।

अध्यक्षः अब आप समाप्त करिये रामदेव बाबू ।

श्री रामदेव राय : महोदय, सभी शिक्षक आज रोड पर है,स्कूल में पढ़ाई बंद है,स्कूल में कोठरी नहीं है,बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएँ कोचिंग में पढ़ते हैं, तो शिक्षित बिहार कहॉ से चला आया ?

अध्यक्षः अब आपका भाषण समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

श्री रामदेव राय: हुजूर, एक मिनट और नहीं दीजियेगा ।

अध्यक्ष: आप तो एक मिनट अपने मन से बढ़ा ही लिये थे ।

श्री रामदेव राय: आप धन्यवाद तो ले लीजिये, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है । बस इतने पर खतम कर दीजिये न ।

श्री रामदेव राय: कर देंगे, कर देंगे । हुजूर, एन0आर0सी0 को ले करके एवं नागरिकता कानून विधेयक को ले करके जो सस्पेंस था, उसको उन्होंने बहुत ही बहादुरी से तर्कपूर्ण ढंग से साफ कर दिये हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है बिहारवासियों की ओर से और आपको भी धन्यवाद कि आपने अपने उर्दू के लहजे से हमलोगों को खुशनसीब बना दिये हैं ।

अध्यक्ष: वह तो पुरानी बात हो गयी ।

श्री रामदेव राय: हुजूर, पुरानी नहीं है परसों की बात है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि अगले दिन आप मैथिली में अपना भाषण हमलोगों को सुना देंगे ।

अध्यक्ष: मैथिली में हम बोले ना बोले बेगूसराय वाली बोली जरुर बोलेंगे ।

श्री रामदेव राय: हुजूर, हमारे भाषण को प्रोसिडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । जो बचा हुआ है, वह दे दीजिये, सदन पटल पर रख दीजिये ।

(परिशिष्ट –2 द्रष्टव्य)

अब माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी । राजू जी आपका समय तीन से चार मिनट है, 3.00 बजे से सरकार का उत्तर होगा ।

श्री राजू तिवारी: ठीक है सर । अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, महामहिम के भाषण में स्पष्ट है कि बिहार मे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे उप–मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज चारों तरफ विकास की गति तेजी से बढ़ रहा है, चाहे हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पोलिटेकनिक कॉलेज हो, सभी अनुमंडल में आई0टी0आई0 हो, ए0एन0एम0 हो, कृषि के क्षेत्र में हों, हर घर बिजली हो, चाहे जितना भी गॉव हो, टोला हो, चाहे सड़क से जोड़ने का हो, बिजली दी जा रही है कृषि के पटवन के लिए यानि की अभी जो भी मूलभूत सुविधा है, वह सारे लोगों को दी जा रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के क्षेत्र में हो, घर–घर शौचालय का हो, नली गली पक्की सड़क की बात हो या हर घर नल का जल की बात हो या अन्य तरह की योजनाएँ हों हमारी सरकार द्वारा हर दरवाजे पर उसे लेकर आगे बढ़ रही है । महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सबों की थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने कुछ दिन पहले देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हुनर हाट में लिट्टी चोखा खा रहे थे, अब लिट्टी चोखा वहॉ खाये लेकिन हमारे यहॉ

के विपक्ष के कुछ साथियों के पेट में दर्द यहाँ शुरु होने लगा, ट्वीट पर ट्वीट होने लगा और अगले दिन हमने देखा कि सत्तू वगैरह ले करके बैठ गये मिडिया के सामने, तो हम कहना चाहते हैं कि इससे तो इनलोगों को खुश होना चाहिए कि हमारा बिहारी व्यंजन जो लिट्टी चोखा है, तो उसका सेवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसमें कष्ट होने की क्या बात है लेकिन जैसे लग रहा था कि चुनाव आ गया है प्रधानंमत्री लिट्टी चोखा, तो मेरा कहना है कि इतना जल्दी विपक्ष को घबड़ाने की बात नहीं है, आने वाले समय में जो फिलगुड में विपक्ष जी रहा है,उनको भी पता चल जायेगा कि आने वाले समय में जनता अपना जवाब देगी और विपक्ष इसको देखेगा । महोदय, तो मैं यह चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वह बड़ी अच्छी भूमिका है, सरकार की जो कमियाँ हैं, उसको दिखावें लेकिन विपक्ष बेवजह, बेबात, अभी कुछ ही दिन पहले विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जायेगा, अरे भाई जब देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आरक्षण के बारे में बोल चुके, तो इनलोगों का काम है टुकड़े-टुकड़े गैंगे को उकसाने का काम करना, ये लोग कभी ..... (व्यवधान)

कहाँ खतम हुआ है,आपलोग बेवजह बात को ले करके देश में भ्रम फैलाने की बात छोड़ दीजिये, भ्रम फैला करके आपलोग समाज को बॉटने का काम कर रहे हैं, जब समय आयेगा, तो इसका जिम्मेदारी भी आपलोगों को लेना पड़ेगा, जिस तरह से आपलोग समय-समय पर देश में कई तरह से अफवाबाजी करके समाज को बॉटने का काम कर रहे हैं, जनता सब देख रही है । इसलिए महोदय मैं यह चाहता हूँ कि विपक्ष सरकार की कमियों को बताये तथा साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी स्वीकार करें । महोदय, आज कहीं भी, आप बिहार के कहीं भी गॉव में चले जाय, पहले एक समय था, हलॉकि हम तो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि माननीय मुख्यंमंत्री जी कहते है बड़े नेता के बारे में, हलॉकि हमें नहीं बोलने का अधिकार है और हम उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था कि रात के 7.00 बजे के बाद कोई अपने घर से निकलता नहीं था लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रात भर हमलोग घूमते हैं,न्योता पेहानी करते हैं,आपलोग चिंता मत करिये, आप ही का राज था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बिहार को एक नये विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं और विकास का कार्य कर रहे हैं,इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उसमें भाग लिया, वैसे सभी माननीय सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता है अपनी तरफ से कोई भी बात रखने को लेकिन हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि महमहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुना है लोगों ने लेकिन कभी वक्त मिले, तो पढ़कर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी लोग जो बोल देते हैं अपराध के मामले में या किसी चीज के मामले में, तो इसपर तो पूरी चर्चा होगी, जब अलग-अलग विभागों पर चर्चा होती है, तो अंतिम दिन गृह विभाग पर चर्चा होती है, तो उसमें जब पूरी चर्चा होगी, तो उसमें सारी बात आयेगी, मैं तो सिर्फ एक ही बात लोगों के ध्यान में ला देना चाहता हूँ कि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसमें उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जो चर्चा की है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा यानि राष्ट्रीय स्तर पर 16 के बाद बहुत विलंब से जारी हुआ है 17 का और 17 के बाद 18 का जारी हुआ है, अभी हाल में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 के अपराध ऑकड़े के अनुसार दर्ज संज्ञेय अपराधों की राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर 383.5 है और उसकी तुलना में बिहार में एक लाख की जनसंख्या पर जो अपराध का औसत है बिहार में, देश भर में 383. 5 है औसत और बिहार का औसत है 222.1 प्रतिशत है ।

क्रमश:

टर्न-10/सत्येन्द्र/26-2-20

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री(क्रमश:)देश के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 23वां है इस सब बात को नहीं भूलना चाहिए लेकिन वैसे चर्चा करने के लिए तो कुछ भी कर दीजिये, इस देश में 23वां स्थान है। अपराध, जो संज्ञेय अपराध की जितनी घटनाएं घटती है तो खैर, कभी इस पर डिटेल चर्चा करनी है, हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं, खुब गौर से सुनेंगे जो वस्तुस्थिति रहेगी उसकी भी जानकारी दे देंगे लेकिन ये तो सब को गौर करने वाली बात है। अब हम कुछ चीजों के बारे में बताना चाहते हैं कि भई आखिरकार सरकार ने जो काम किया है और एक तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और दूसरा कल जो माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बहुत सारी बातों की चर्चा की है उसको भी कभी गौर से पढ़ लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई

नहीं है बोलने के लिए तो जो भी इच्छा हो बोलिये। अब आप जान लीजिये, यह जो सात निश्चय की बात हमलोगों ने कही और उस पर जो काम शुरू किया तो उसमें 24 फरवरी, 2020 तक इन योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की हम जानकारी दे देना चाहते हैं। जो पहला था, युवाओं से संबंधित आर्थिक हल युवाओं को बल, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उसका पांच कम्पोनेंट है, उसमें 73,141 छात्र छात्राओं को 850 करोड़ 76 लाख रू0 का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, 4 लाख, 14 हजार 510 युवाओं को 497 करोड़ 10 लाख रू0 वितरित किये गये। कुशल युवा कार्यक्रम, जो कुशल युवा कार्यक्रम की हमलोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कम्प्यूटर पर काम करना लोग सिखते है, भाषा के बारे में भी उनको बतलाया जाता है और व्यवहार कौशल, किस तरह से व्यवहार किया जाय इसके बारे में जो हमलोग उनको पूरा प्रशिक्षित करते हैं और कुशल युवा कार्यक्रम में पूरे बिहार में 1 हजार, 717 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं, संचालित हैं । अब तक 9 लाख 50 हजार 264 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और अभी 89 हजार 406 युवाओं का प्रशिक्षण जारी है फिर 500 करोड़ रू0 के बेंचर कैपटल फंड का गठन एवं इक्योवेशन सेंटर की स्थापना की गयी । इसका भी काफी इसमें 11हजार 712 आवेदन प्राप्त हुए उस पर आखिर काम आगे बढ़ता चला गया, 1 हजार, 381 स्टार्टअप इक्योवेशन हेतु पोस्ट संस्थान के साथ सम्बद्ध किया गया, बहुत लोगों को दिया गया । किन्हीं को प्रथम किस्त का, किन्हीं को द्वितीय किस्त का भी भुगतान किया गया है और जो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सरकारी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जो हमलोगों ने कहा था कि नि:शुल्क वाई फाई की सुविधा देंगे, आज की जो टेक्नोलोजी है उसका फायदा लोग उठायेंगे तो 320 से अधिक संस्थानों में यह उपलब्ध करा दिया गया और अभी प्रति संस्थान, हर संस्थान में औसतन 284 यूजर नि:शुल्क वाई फाई का उपयोग कर रहे हैं तो एक जो हमलोगों का निश्चय था उसके अन्तर्गत ये हुआ और दूसरा तो सबको मालूम है कि महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण तो फरवरी, 2016 से ही लागू कर दिया गया। फिर तीसरा था हर घर बिजली, उसकी निर्धारित समय सीमा थी दिसम्बर 2018, उसके दो माह पूर्व अक्टूबर 2018 में ही सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कर दिया गया, 1 करोड़ 19 लाख इच्छुक घर थे उनको प्रदान कर दिया गया और बिजली की स्थिति की बात कर दी जाती है लेकिन आप जान लीजिये 2005 में पूरा जो बिजली की खपत थी पूरे बिहार में वह था 700 मेगावाट या मांग कह लीजिये और अब वह बढ़कर हो गयी है 5891 मेगावाट, फिर उसके बाद हमने कह दिया था कि जितने हमारे पूराने जर्जर तार हैं उनको बदला जायेगा और यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि

जर्जर तार को भी बदल दिया गया और इसके अन्तर्गत 72 हजार 331 किलो मीटर जर्जर तारों को बदला गया जिसमें 3070 करोड़ रू0 खर्च हुआ। दिल्ली की बात होजाती है, दिल्ली में जो अभी घटना घटी, आग जो लगी तो जरा दिल्ली के मुख्य सड़कों को छोड़कर अन्दर में चले जाईयेगा, राजधानी है और जाकर जरा देख लीजिये कि वहां किस तरह के जर्जर तार है, एक साथ 4-5 तार लटका हुआ है और उसी में घटना घटती है तो ये स्थिति समझ लीजिये और हमलोगों ने अपने बिहार में एक पिछड़ा राज्य है एक गरीब राज्य है, बहुत ज्यादा आबादी वाला राज्य है और वहां हमलोगों ने सारे जर्जर तार को बदल दिया और उसके बाद एक संकल्प लिया कि भाई हमलोग कृषि फीडर के माध्यम से जो इच्छुक किसान हैं उनको बिजली की आपूर्त्ति करेंगे । उस पर भी काम जो पिछले वर्ष का तारीख तय किया गया था कि उस समय तक जिनका आ जायेगा आवेदन, उसको पूरा कर दिया जायेगा उसके बाद जो होंगे उसको इसके बाद पूरा किया जायेगा तो जितना लोगों का था उसका लक्ष्य है हमलोगों का कि 2020 के मार्च तक पूरा कर दिया जायेगा और इस कार्य के लिए जो कृषि फीडर के लिए हमलोगों ने 5 हजार, 827 करोड़, 23 लाख रू0 की राशि स्वीकृति दी है और इसके तहत निर्माणाधीन 267 विद्युत उपकेन्द्रों में से 202 एवं 1 हजार 312 पृथक फीडरों में 1 हजार, 114 का निर्माण किया जा चुका है और वर्त्तमान तक 1 लाख 36 हजार 500 किसानों को विद्युत सम्पर्कता प्रदान की गयी यानी पूरा तेजी से वह काम भी हमलोग कर रहे हैं और कृषि कार्य के लिए हमलोगों ने बिजली का दर घटाकर के मात्र 75 पैसा किया और एक बात मैं कहूंगा बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता है और यह काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 यूनिट तक हम दे देंगे फ्री इसको और बिजली मुफ्त में और उसकी क्या स्थिति होने वाली है यह किसी को पता नहीं है । बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए और इतना हमलोग जो पर्यावरण के लिए सारा काम कर रहे हैं लेकिन मात्र 75 पैसा, आप कल्पना कर लीजिये, मात्र 75 पैसा में दे रहे हैं हमलोग आपको आपूर्त्ति कर रहे हैं एक यूनिट का और अब जब इतना सब कुछ कर दिया है तब हमलोगों का जोर है सौर ऊर्जा पर और उस पर बहुत तेजी से काम हमलोगों ने प्रारम्भ कर दिया है । जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत उसका काम शुरू हो गया है। अब नल का जल- अब जरा ठीक से सुन लीजिये। हर घर नल का जल जो हमारा है चौथा निश्चय, अब जरा उसकी जानकारी जान लीजिये । ग्रामीण व शहरी बार्डो में निर्माण की स्थिति हम बतला देते हैं । पंचायती राज बार्डो में लक्ष्य कितना है

58,326 बार्ड का लक्ष्य है और काम पूरा हो चुका है 38,410 बार्ड में, कार्य जारी है 19,324 बार्ड में और प्रक्रियाधीन है, अब मात्र बचा है 582 बार्ड और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है वहां पर उसके माध्यम से काम कर रहे हैं और किसी भी पंचायत का कुछ बार्ड जो गुणवत्ता प्रभावित था वहां पूरे पंचायत के लिए हमलोगों ने जिम्मा पी0एच0ई0डी0 को दिया कि आप ही इस काम को कीजिये तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास लक्ष्य दिया गया था जो ग्रामीण बार्ड है 56,079 और काम पूरा हो चुका है 9600 बार्ड में, काम जारी है 42,754 बार्ड में और प्रक्रियाधीन है मात्र 3,725 बार्ड ,यह रूलर एरिया की बात हो गयी । अब अर्बन एरिया की बात सुन लीजिये । नगर विकास एवं आवास विभाग, इसका बार्ड का पूरा का पूरा लक्ष्य है पूरे बिहार में 3370, काम पूरा हो चुका है शहरी इलाकों में भी 1099, काम जारी है 1832 और प्रक्रियाधीन है मात्र 439 तो कुल मिलाकर के कितने बार्ड में काम करना था शहर और गांव का मिलाकर के उसमें 1 लाख, 17 हजार 775, काम पूरा हा गया है 49 हजार, 109 काम जारी है 63,920 और प्रक्रियाधीन है 4,746, ये स्थिति है (क्रमशः)

टर्न-11/मधुप-हेमंत/26.02.2020

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह स्थिति है और हमलोगों का लक्ष्य है कि जून तक इन सब काम को पूरा करा देंगे । हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण - यह हमारा पाँचवाँ निश्चय है । पंचायती राज में लक्ष्य वार्ड का है - 1,14,691 और उसमें से 75,701 वार्ड में काम पूरा हो गया, 25,277 वार्ड में काम जारी है और प्रक्रियाधीन है - 13,713 वार्ड। नगर विकास और आवास का, लक्ष्य है - 3,371, काम पूरा हो गया है - 1,103, काम जारी है - 2,238 और प्रक्रियाधीन है - 30 । अब यह जान लीजिए कि यह लक्ष्य है, उसको भी इस साल हमलोग दिए हुए हैं टारगेट कि जून तक इसको पूरा कर लेंगे । इसके अलावा ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना- इसमें कुल लक्षित 4,683 टोले थे, 4,133 टोलों के पथों का निर्माण कर सम्पर्कता दी जा चुकी है । अब शेष 510 टोलों पर कार्य प्रगति पर है । इसमें 346 टोलों की योजनाएँ मार्च, 2020 तक पूर्ण की जाएगी । शेष 164 टोलों के लिए रैयती भूमि की सतत लीज पर लेने की कार्रवाई जारी है और इन योजनाओं को जून, 2020 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है । शौचालय का निर्माण घर का सम्मान - सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाय ।

उसके बाद जो इंस्टीच्यूशन्स बनाने का था, अवसर बढ़े - आगे पढ़ें । कितने इंस्टीच्यूशन्स की स्थापना हो गई । सभी संस्थानों की स्थापना हेतु लगभग सभी जगह चिन्हित कर ली गई हैं । संस्थान की स्थापना की जा रही है, भवन निर्माण के कार्य विभिन्न चरणों में हैं । सात निश्चय के अन्तर्गत 33 पारा-मेडिकल और 5 फार्मेसी संस्थानों की स्थापना की जा रही है । प्रत्येक जिला में जी0एन0 संस्थान के अतिरिक्त 38 के विरूद्ध 10 जिलों में संचालित, 5 जिलों में निर्माणाधीन, 20 जिलों में निविदा की प्रक्रिया में, 2 जिलों में डी0पी0आर0 का निर्माण और एक जिला बेगूसराय में भूमि चिन्हित की जा रही है । प्रत्येक अनुमंडल में ए0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 101 के विरूद्ध 47 अनुमंडलों में पूर्व से संचालित, 52 स्थलों की निविदा प्रक्रियारत एवं 2 स्थलों पर, डुमराव एवं तेघड़ा में भूमि का चयन किया जा रहा है । सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है । सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज के पठन-पाठन हेतु सत्र संचालित हो गए हैं, 15 जिलों में अपने भवन में पढ़ाई हो रही है, शेष 23 जिलों में भवन निर्माणाधीन है, जहाँ पढ़ाई अस्थाई परिसर से की जा रही है, भवन का निर्माण चल रहा है । इंजीनियरिंग कॉलेज सभी 38 जिलों में खुल गया । 38 जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान में पठन-पाठन हेतु सत्र संचालित है, 19 जिलों में अपने भवन से पढ़ाई, 12 का निर्माण पूर्ण, 6 जिलों में भवन निर्माणाधीन और एक जिला जहानाबाद में भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है । सभी 101 अनुमंडलों में आई0टी0आई0 के पठन-पाठन हेतु सत्र संचालित है । सभी 38 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी महिला आई0टी0आई0 में पठन-पाठन हेतु सत्र संचालित है । 7 जिलों में अपने भवन से पढ़ाई, 7 का निर्माण पूर्ण, 22 जिलों में भवन निर्माणाधीन तथा 2 जिले - गोपालगंज एवं लखीसराय में भूमि हस्तांतरण प्रक्रियारत है । अब यह सात निश्चय का एक-एक डिटेल हमने आपके सामने बता दिया और लक्ष्य रख दिया, जो काम करने का वादा किया जाता है उस काम को पूरा करना हमलोगों का लक्ष्य होता है ।

अब आपको हम कितनी बातों की जानकारी दें ! हमलोगों ने कितना काम शुरू करवाया, अनेक स्तर पर काम शुरू किया । जितना भी छात्रावास - सरकारी छात्रावास अनुदान, मुफ्त में 15 किलो अनाज 1 हजार रूपये का प्रतिमाह करना और जितने हमारे पुराने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास जर्जर स्थिति में हैं, 19 नये भवनों का तथा 14 छात्रावासों को विशेष मरम्मति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । हर प्रकार से काम शुरू किया गया । मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना - हरेक ग्राम पंचायत में 5 परिवहन की व्यवस्था हमलोगों ने की है । 3 दिया गया

है अनुसूचित जाति/जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को । कितना इसका काम पूरा हो चुका है - 41,930 के विरूद्ध 22,500 लाभुकों को अनुदान वितरित किया गया है । अब इस योजना में ई-रिक्शा को भी शामिल किया गया है । जितने स्कीम्स हैं, हर तरह से किया गया है । अब जो केन्द्र सरकार के द्वारा एक जो संचालित है, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना, जो अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए है, उसमें है कि जिस परिवार की आमदनी 2. 5 लाख रू0 तक है, उनको मिलता है और अन्य पिछड़े वर्गों में यह मिलता है उन परिवारों तक जिनकी आमदनी है 1.5 लाख रू0 का । उसमें हमलोगों ने तय किया कि अति पिछड़े वर्ग के लिए भी 2.5 लाख रू0 तक की आमदनी वाले परिवार के बच्चे-बच्चियों को देंगे और यह हमलोगों ने अपनी तरफ से इसका काम शुरू कर दिया है, इसकी योजना हमलोगों ने कर दिया है । जिस तरह से अनुसूचित जाति/जनजाति है, उसी की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख रू0 के बीच की आमदनी वाला जो परिवार है, उनके बच्चे-बच्चियों को यह छात्रवृति अब राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी । काफी काम किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसका नाम छूट गया, उसको मुख्यमंत्री आवास योजना से हमलोग करने जा रहे हैं, उनको भी 1 लाख 20 हजार रू0 का, जो 1996 तक का, पुराना जो है, जर्जर हो गया, उसको बिल्डिंग बनाने के लिए हमलोगों ने दिया है । प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि नाम है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रू0 का प्रावधान कर दिया गया है कि इसका लाभ ले लीजिए । जरूरत पड़ेगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसको और बढ़ाया जा सकता है । हमलोग चाहते हैं कि सबका मकान बन जाय, सबका आवास बन जाय और बचे हुए लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस काम को कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

जमीन कहाँ से मिलेगा आपको-सबको ? बैठिए न ! आप माले के हैं, आपका तो काम ही है ऐसे ही बोलते रहने का । माले को कुछ पता है ? इनको बैठाइये जरा, हम अभी इनको बताते हैं । अब सुनिए जरा । (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न । आप जानकारी ग्रहण करिए न ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इनलोगों का काम सब हमलोग कर देते हैं लेकिन रोज कुछ बोलना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप तो कह लिये, अब तो बैठ जाइये । आप तो सूचना दे दिये न, अब बैठ जाइये।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और कुछ बोलना है, फिर बोलना है ? बैठ जाइये और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिये । अपने बिहार की स्थिति को सबको समझना चाहिए । यह जो बिहार का क्षेत्रफल है या किसी राज्य का क्षेत्रफल है, वह तो नहीं न बदलेगा - 94 हजार वर्ग कि0मी0 और आबादी कितनी हो गई है, अब 12 करोड़ के करीब हो गई होगी, जनगणना होगी तब पता चल जायेगा कि क्या स्थिति है, जितना इसका बढ़ता है, रेट जो रहता है, उसके हिसाब से लगभग हो गया होगा । अब जरा कल्पना कर लीजिए, आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन तो वही सीमित है, आपलोग खाली अगर कहिएगा कि इतना जमीन दो, तो कुछ आसमान से आ जाय जमीन ! तभी न दीजिएगा । यह सब सिवाय जिसको कहिए बकवास के... (व्यवधान) मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, अगर बकवास उचित नहीं है तो हम वापस ले लेंगे लेकिन है यह बकवास । जब कोई डिमांड करता है कि इसको इतना जमीन दीजिए । जमीन रहेगा तब न कोई देगा ! जमीन है ही नहीं इस बिहार में तो इसीलिए कह रहे हैं हमलोग कि पैसा देंगे कि वह जमीन खरीद ले। आप कहॉ से जमीन लाइयेगा ? जमीन के एक्वीजिशन का रेट क्या है और रेट बढ़ता चला जा रहा है । इसलिए आदमी को आप पैसा दीजिए और घर बनाने के लिए उसको अभी 60 हजार दे रहे हैं और जरूरत पड़ेगा तो उसको हम 1 लाख भी दे देंगे लेकिन जमीन खरीदो भाई । जमीन खरीद लो और आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रू0 दे रहे हैं । आप जाकर लोगों को कहिए लेकिन आप तो कहिएगा नहीं... . (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आपको तो जुलूस निकालना है, आपको तो जुलूस में लेकर सबको आना है ।

दूसरी चीज हम बता दें, जो योजना हमलोगों ने शुरू की, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना - अब इसमें क्या हमलोगों ने किया था कि 10 लाख रू0 तक की सहायता देंगे, 5 लाख रू0 ब्याज सहित ऋण और 5 लाख रू0 अनुदान देंगे । यह काम हमलोगों ने शुरू कर दिया था ।

...क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/26.02.2020

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : यह काम हमलोगों ने शुरू कर दिया था और उसके बाद अब इसका विस्तार कर दिया गया है अति-पिछड़ा वर्ग के लिए भी और अब इसका

नामकरण हो गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति-पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के रूप में । आप सोच लीजिए, यह तो 10 लाख रू0 मदद की बात हो गई, 5 लाख अनुदान एवं 5 लाख ब्याजरहित ऋण । ऋण जो ब्याजरहित है तीन खंड में पैसा उनको मिलता है, जब उनको पूरा पैसा मिल जायेगा और जब काम शुरू कर दिया तो उसको एक साल के बाद जो ब्याजरहित ऋण है, उसको 84 खंड, किश्तों में लौटायेंगे, वर्षों-वर्षों तक उनको अवसर दिया गया है । जान लीजिए, जो ऋण दिया गया है ब्याजरहित, वह भी एक प्रकार की सहायता है । कहीं दूसरी जगह से इस प्रकार से ऋण उनको मिल सकता है, जो ब्याजरहित हो और उनको इतना समय दिया जाता हो ? इसको कम से कम समझ लीजिए कि 10 वर्ष मिनिमम, यह मामूली बात नहीं है और इसका विस्तार अब अति-पिछड़ा वर्ग के लिए भी कर दिया गया है ।

इसलिए हर चीज के मामले में हमलोगों ने यह काम करना शुरू कर दिया है और कोई भी क्षेत्र में जिस चीज के बारे में हमलोगों ने बात किया है, न्याय के साथ विकास का, उसको याद रखते हैं । अब सामाजिक विकास के बारे में जरा जान लीजिए । वृद्धजन पेंशन योजना शुरू किया न । अब वृद्धजन पेंशन योजना में चाहे उनकी कोई भी आमदनी रहे, जो बचे हुए लोग हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई हो स्त्री या पुरूष की, उनको राज्य सरकार पेंशन देगी । हमलोगों को जो उम्मीद थी कि 25-26 लाख लेकिन कुल आवेदन मिला 19 लाख, अब तक 19 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं । जिनकी इच्छा है, बहुत लोगों के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होगी । 19 लाख आवदेन आया, जिसमें 14 लाख 21 हजार लाभुकों को स्वीकृति प्रदान कर भुगतान कर दिया गया है, 2 लाख 10 हजार आवेदकों को एक सप्ताह में स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी, शेष लगभग 2 लाख 70 हजार की स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है । अब जरा जान लीजिए और कई जगहों पर होता है, जो बायोमेट्रिक सत्यापन की बात है, जिसमें लोग ऊँगली का लेते हैं, अब उसमें बहुत लोगों का है कि उनके उम्र हो जाने के बाद मिल नहीं पाता है, इसलिए उनको यह अवसर नहीं मिलता है, अब इसमें हमलोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । बायोमेट्रिक सत्यापन में कतिपय मामलों में सफल नहीं होने की स्थिति में प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन की सुविधा भी दी जायेगी, फिजिकली मौजूद रहेंगे, वही सत्यापन हो गया कि इन्हीं को मिलना है । अब इसकी जरूरत बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी और स्वीकृति की स्थिति अथवा पुराने पेंशनधारियों की पेंशन भुगतान की सही-सही जानकारी हेतु अब प्रखंड स्तर पर जो लोक सेवा केन्द्र है, उसमें एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है । किसी को कोई

समस्या हो, जो लोक सेवा केन्द्र है प्रखंड के स्तर पर, वहां पर हेल्प डेस्क होगा, अब किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी । जिनको मिल रहा है, अगर उनको किसी तरह की दिक्कत होगी, वे वहां पहुँच जायेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी । हर तरह की सुविधा हमलोग कर रहे हैं तो एक-एक चीज है ।

अब स्वास्थ्य के बारे में, अब जान लीजिए कि स्वास्थ्य के बारे में इतना काम हुआ है, हां हम आ रहे हैं चमकी बुखार पर, पूरी बात बता देंगे हमारा यह फर्ज है । पिछले साल इसपर डिवेट हुआ, ऐसे ही था बजट का, हमलोगों ने तुरंत कहा कि इसको स्वीकार कीजिए और उसपर बहस हुई और उसके बाद हमने इसपर जो काम किया, हमारा कर्त्तव्य बनता है न कि हम जानकारी सदन को जरूर दे दें, जब इसपर बहस होगी स्वास्थ्य विभाग पर तो इसपर और विस्तार से बतायेंगे। लेकिन सीमित रूप में कुछ जरूरी चीजों को आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह से हमलोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया । आप जान लीजिए 2005-06 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आऊटडोर में जो पेशेंट आते थे, उसका हमलोगों ने सरकार में आने के बाद ही तुरंत सर्वेक्षण कराया, 39 लोग ही महीना में आते थे, यानी एक दिन में एक मरीज या एक के बजाय दो मरीज आ जाते थे और अब प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यह संख्या बढ़कर के हो गई है प्रतिमाह 10हजार जान लीजिए । दूसरी बात है मातृत्व मृत्यु दर की क्या स्थिति थी, प्रति लाख जनसंख्या पर वर्ष 2005-06 में 371 थी यानी प्रतिलाख जनसंख्या पर कितने मातृत्व दर होते हैं तो 2005-06 में 371 और वर्तमान में यह घटकर आ गया है 165 पर, 2005-06 में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जनसंख्या पर जो 61 थी, वह घटकर 35 हो गई है । 2005 में कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 4.3 था, जो अब 2016-17 में यह घटकर 3.2 पर पहुँचा है । वर्ष 2006 में औसत आयु लाईफ एक्सपेटेंसी 61.6 वर्ष था, अब 2014 आते-आते, 2014 के आगे अभी केन्द्र का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, 2014 में यह बढ़कर हो गया है 68.1 वर्ष, ऐसे पता है अभी फॉरमल एनाऊंसमेंट नहीं हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट आती है, वह 70 के ऊपर जा चुका है । इसमें महिलाओं का उम्र ज्यादा है और पुरूषों का उम्र कम है । यह स्थिति है जरा जान लीजिए औसत उम्र के बारे में । नियमित टिकाकरण इसके बारे में भी जरा जान लीजिए, 2006 में नियमित टिकाकरण मात्र 18 प्रतिशत था जो अब बढ़कर हो गया है 86 प्रतिशत, हमलोगों का लक्ष्य है कि सम्पूर्ण टीकाकरण करायेंगे और टिकाकरण के क्षेत्र में बिहार टॉप फाईव स्टेट में रहेगा, यह हमलोगों का लक्ष्य है और इसपर काम हो रहा है । अब इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने, जिला अस्पताल बना, सब कुछ हुआ। अब एक चीज हम कहना चाहते हैं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक भूमि सरकार को दान में दे सकते हैं तथा उक्त स्वास्थ्य संस्थानों का नामकरण उनके परिवार के द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जा सकेगा । वैसे जहां पर जमीन मिलती है, बन चुका है। आप समझ लीजिए कि कुल स्वीकृत 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1399 कार्यरत है, 153 का निर्माण 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा शेष को 3 वर्षों में चरणवद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा । हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा । इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से 7 लाख रू0 की मदद भी मिलेगी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये सारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हमलोग कन्वर्ट करेंगे तो यह हमलोगों का निर्णय है । इस तरह से किसी भी क्षेत्र में अब एक बात बहुत जरूरी है, जो ए0ई0एस0 है, एक्यूट इन्सेफलाईटिस सिन्ड्रोम, जो मुजफ्फरपुर जिला से संबधित मामला था । 24 दिसम्बर, 2019 को मुजफ्फरपुर जिला के ए0ई0एस0 प्रभावित कांटी प्रखंड के पानापुर हवेली का हमने भ्रमण भी किया, जो जल, जीवन, हरियाली यात्रा में थे, हम वहां भी गये जान-बुझकर के, क्योंकि हमने कहा था कि इसका सोसियो इकोनॉमी सर्वे कराईए और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस घटना ए0ई0एस0 से 5 प्रखंड मुजफ्फरपुर जिले का, जिसमें हम एक जगह गये, जहां पर हमने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उस दिन हमने मीटिंग भी की, समीक्षा बैठक भी की । 2019 में मुजफ्फरपुर जिले में 731 बच्चे ए0ई0एस0 से प्रभावित हुए थे, जिसमें 111 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, 320 बच्चों को उपचारित करके बचाया गया था और 5 प्रभावित प्रखंड बोचहा, मोतीपरु, मीनापुर, कांटी, मुशहरी तो सबका आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया । अब जो स्थिति है, जान लीजिए सोसियो इकोनॉमी सर्वे कराने के बाद, जो सर्वे की रिपोर्ट आयी, हमने विभिन्न विभागों को यह जिम्मेवारी सौंपी कि यह काम करना है, उसके सोसियो इकोनॉमी स्थिति में सुधार आना चाहिए, इसके लिए ग्रामीण विकास को जिम्मा दिया गया कि जीविका द्वारा छुटे हुए सभी योग्य 7082 परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है । यानी उसमें जो परिवार जुड़ा हुआ नहीं था, उसमें जोड़ने के लिए 7082 परिवारों को । सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कुल 2578 परिवारों का चयन किया गया है, मार्च महीना के अंत तक उक्त प्रखंडों के समस्त योग्य परिवारों को रोजगार हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ दिया जायेगा । आप जानते हैं जो उनको मदद की जा रही है 60हजार रू0 से 1लाख रू0 तक, कोई भी अपना काम करना शुरू कीजिए ।

..... क्रमशः .....

टर्न–13/शंभु/26.02.20

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः..और उसके लिए काम हो रहा है, हर परिवार के लिए पांचों प्रखंड में सोशियो इकोनोमिक सर्वे के बाद जो निर्णय लिया, ऐसे ही खाली नहीं करते हैं । उसका एक–एक काम हो रहा है । उसकी समीक्षा की और ये अब पूरा का पूरा होगा । जीविका दीदीयां, आशा और ए0एन0एम0 की मदद से 13194 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों एवं अन्य परिवारों को ए0इ0एस0 से बचने, खानपान पर ध्यान एवं चमकी बुखार होने पर क्या करें और कहां जाएं इसकी जानकारी दी जायेगी । कम्युनिटी रेडियो, ग्राम वाणी की मदद से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जानकारी प्रदान की जा रही है । अभी तक लक्ष्य 29598 के विरूद्ध 28322 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दे दी गयी है । जो आवासहीन जितने हैं सबको आवास हम प्रदान करेंगे, आप यह जान लीजिए तो इतने को स्वीकृति 29598 लक्ष्य के विरूद्ध 28322 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दे दी गयी है और 20377 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त कर दी गयी है, शेष लाभार्थियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है । ए0इ0एस0 प्रभावित प्रखंडों में बेस लाइन सर्वे में शामिल सभी 1 लाख 91 हजार 732 परिवारों को शौचालय से आच्छादित किया गया है । बेस लाइन से छूटे हुए सभी 37825 परिवारों को भी शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । इसके अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण विभिन्न चरणों में है ।

अब स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या किया गया– जो मुजप्फरपुर आसपास के लोग प्रभावित होते हैं तो श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 62 करोड़ की लागत से 100 शैय्या वाले शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई मई, 2020 तक कार्यशील कर दिया जायेगा । यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो बहुत ही सीरियस बीमार है उसको इसमें भरा जायेगा । पी0आइ0सी0यू0 पेडियाट्रिक इन्सेंटिव केयर यूनिट उसके लिए 100 बेड का निर्माण किया जा रहा है । हम तो गये थे वहां देख आये हैं सारा काम चल रहा है । अब एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कार्यशील कर दिया तो कार्यशील कर दिया जायेगा । इसके अलावे दरभंगा, पटना, मुजप्फरपुर, भागलपुर और आर0एम0आर0आइ0 जो केन्द्र की संस्थान है । पटना में विरल रिसर्च ऐंड डायगोनेस्टिक लैब कार्यशील कर दिया गया है । अब यह सब लेबोरेट्री को भी कार्यशील कर दिया गया है ताकि सब चीज की जानकारी, लोगों का टेस्ट हो जाय तथा विशेषज्ञ सहायता हेतु नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरो साइन्सेज बेंगलुरू के साथ तकनीकी सहायतार्थ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है । ये जो शराबबन्दी लागू किये और उसके बाद जो पीते थे उनको

दिक्कत हो रहा था तो उसके लिए जो सब जगह हास्पीटल बनवाये थे उसके भी डाक्टर्स को और सबको ट्रेनिंग करने के लिए हम यहीं भेजे थे नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरो साइन्सेज- लागू करने के पहले ट्रेनिंग कराकर के तब सभी 38 जिला में इसको बहाल किये थे । उसी के साथ एग्रीमेन्ट किया है कि किसी भी प्रकार का जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना रहता है या व्यवस्था करनी रहती है, कोई टेस्ट करना हो उसमें हर तरह का इंतजाम हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है । जिला प्रशासन की ओर से सभी ग्रामीण हाट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं मुख्य चौराहों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है एवं इसका प्रचार-प्रसार भी किया गया है । अनेक जगह पर एम्बुलेंस रहेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई हो तो तत्काल वह अस्पताल उचित जगह पर पहुंच सके और कार्ययोजना के अनुसार अर्ली वार्निंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है जो ए0इ0एस0 प्रभावित मरीजों को शीघ्र पहचान में मदद करेगा । यह व्यवस्था सभी मरीजों तथा स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने एवं रेफरल सेवा में मददगार साबित होगा । राज्य में दूसरा जो है जे0इ0 जेपेनिज इन्सेफलाइटिस से बचाव हेतु टीकाकरण शुरू किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे बैठिए न, ऐ रविन्द्र जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : उनको समझ में आये न आये आप समझने की कोशिश कीजिए न, जरा गौर से सुन लीजिए । ये जो गया और कई जगहों पर होता है जेपेनिज इन्सेफलाइटिस....

(व्यवधान)

अरे भाई बोलना हो, अरे हम कर दिये न, हम ही न कह दिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, आप रविन्द्र जी की इच्छा क्यों पूरी कर रहे हैं । आप अच्छा से सुन रहे थे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुनिए जेपेनिज इन्सेफलाइटिस जो गया वगैरह में इतना जानने सुनने को मिलता था जे0इ0 उससे बचाव हेतु उसका टीकाकरण कर रहे हैं अधिकांश जगहों पर और यह टीकाकरण जे0इ0 से बचाव के लिए, जेपेनिज इन्सेफलाइटिस से बचाव के लिए जो टीकाकरण हो रहा है वह टीकाकरण 77.31 प्रतिशत बच्चों को किया गया है और अगले दो महीने में लक्ष्य है कि संपूर्ण टीकाकरण पूरे बिहार में करा दिया जायेगा । इसलिए ऐसा मत समझिए कोई बीमारी होती है तो हमलोग उससे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है उसपर गौर करने के बाद जो भी संभव है वह काम करने के लिए तैयार रहते हैं । खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग को जिम्मा दिया गया कि खाद्य आपूर्ति के लिए

जितने परिवार पांच प्रखंडों में छूटे हुए हैं उनकी सूची तैयार कीजिए, तैयार कर दी गयी, पंजीकरण का कार्य भी कर दिया गया है और विकास मित्रों की मदद से विशेषकर महादलित परिवारों की सूची तैयार की गयी और कैंप लगाकर 20668 योग्य परिवारों को राशन कार्ड का वितरण किया गया है । इन पांच प्रखंडों में क्या था जब सोशियो इकोनोमिक सर्वे कराया तो वहां की जो स्थिति पता चली उसके बाद एक-एक काम करवा रहे हैं कि कोई भी आदमी को राशन की दिक्कत न हो तो इस प्रकार से किया गया । फिर शिक्षा विभाग में नामांकन योग्य सभी बच्चों की सूची तैयार की गयी ड्रॉप आउट जो छोड़कर के निकल गया उसपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और विभाग द्वारा उन पांच प्रखंडों के सभी विद्यालयों में

(व्यवधान)

अरे सुन तो लीजिए उसके बाद बोलियेगा । अब आप जान लीजिए शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विद्यालयों में उन पांच प्रखंड के जितने भी विद्यालय हैं जिसमें मध्याह्न भोजन होता है उस मध्याह्न भोजन के साथ उन पांच प्रखंडों में सभी बच्चे-बच्चियों को दूध उसके साथ देने के काम पर कार्रवाई की जा रही है । उन बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जो दिया जाता है मध्याह्न भोजन उसमें दूध भी उन सब लोगों को उपलब्ध करायेंगे । ये जरा जान लीजिए एक-एक चीज और फिर समाज कल्याण विभाग के द्वारा ए0इ0एस0 प्रभावित पांच प्रखंडों में कुल 1671 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं । अब उसमें जो छूटे हुए थे सभी योग्य बच्चों के पंजीकरण हेतु उसके अतिरिक्त यानी 1671 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त 303 नये आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं साथ ही कैंप के माध्यम से पोषण, स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान भी चलाया गया है । आप यह समझ लीजिए हर घर नल का जल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा कुल 261 वार्डों के विरूद्ध 241 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 20 वार्डों में कार्य प्रगति पर है । पंचायती राज विभाग के द्वारा कुल 1429 वार्डों के विरूद्ध 810 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 588 वार्डों में कार्य प्रगति पर है । यानी हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण 38 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जाना है । सभी वार्डों में यह कार्य मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा । अब आप समझ लीजिए कि जब घटना घटती है, वर्षों से घट रही है ए0इ0एस0 की लेकिन इस बार जो हमलोगों को चिंता हुई और सोशियो इकोनोमिक सर्वे कराया और सोशियो इकोनोमिक सर्वे के बाद हमलोगों ने कार्य योजना बनाकर के उसका क्रियान्वयन इस तरह से किया जा रहा है । इसलिए जरा इन बातों पर भी गौर कीजिए, बोलने के लिए तो स्वतंत्रता है । अब कहीं के लिए भी किसी के लिए भी बात करें तो कितना ज्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में- शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी जब हमलोग

काम संभाले थे साढ़े 12 परसेंट बच्चे-बच्चियां स्कूलों से बाहर थे और उनको लाने के लिए कितना स्कूल बनवाया, कितने टीचर का रिक्रूटमेंट किया, क्या नहीं हमलोगों ने किया ।

क्रमशः

टर्न-14/26-02-2020/ज्योति

क्रमशः

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : 21,264 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए । 16,346 नये भवन बनाये गये । बहुत सारे भवन में भवन के साथ ही एक्वायर किया जाता है, 16,346 नये विद्यालय भवन बनाये गये । शेष नजदीक के स्कूल अन्य भवनों में संचालित हैं 19,625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 2 लाख 77 हजार 403 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाये गये । अब आप जरा बताइये कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको पढ़ाने के लिए 12.5 बाहर रहता था, अब 1 परसेंट के अंदर है और उन लोगों की स्थिति को देखते हुए ही सारा काम किया गया । क्या काम किया गया, टोला सेवक, तालिमी मरकज स्वयंसेवक- ये सब के माध्यम से जो सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर थे, वे या तो महादलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उनको घर के बाहर पढ़ाकर के 3-4 साल के बाद इतना बड़ा काम किया गया । टोला सेवक और तालिमी मरकज स्वयंसेवक और इस तरह की स्थिति आई कि 1 परसेंट से भी कम हो गया । अब कहने के लिए तो लोग जो चाहे वह कहे । कहने के लिए तो जिसको मर्जी आवे, उतना कहता रहे । काम जो हो रहा है, उसको भूल जा रहे हैं । कल तो हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के बारे में बता दिया कि पहले कौन सा स्कूल चल रहा था । फिर क्या हुआ, तो यह सब बता चुके । हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बातें हैं और जान लीजिए हम लोगों ने क्या किया । जो फर्टिलिटी रेट है आपको बता दिया 4.3 से 3.2 पर आया है, लेकिन जब हमलोग मानव विकास मिशन बनाए और 5 प्वायंट पर लोगों की सहायता करने के लिए तो उसमें हमलोगों ने स्थिति का आकलन किया और स्थिति के आकलन के मुताबिक ..

(व्यवधान)

(इस अवसर पर मा0 सदस्य श्री सत्यदेव राम सहित सी.पी.आई(माले) के सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन से बाहर जाने लगे)

अध्यक्ष : आपलोग जब सदन में थे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हड़ताल पर इनको भी रहना चाहिए ।

अध्यक्ष : सदन में बोल ही रहे थे । जा रहे हैं तो शाांति से जाईये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अभी रहियेगा और हड़ताल पर नहीं जाइयेगा तो पूरा हड़ताल पर हम लम्बी बात कह देंगे हमको नहीं मालूम है कि कितना मिनट लगेगा, इसलिए अच्छा है कि हड़ताल पर चले जाइये नहीं तो कितना सुनियेगा ।

अध्यक्ष : अब तो जा ही रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : जब इस फर्टिलिटी के बारे में आकलन किया और हम सब जगह बताते रहते हैं जो उसके बारे में सर्वे कराया गया तो साहब यह पता चला कि अगर पति-पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में उस परिवार का प्रजनन दर औसत 2 है और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो यहाँ का भी प्रजनन दर 2 है उस परिवार का और उस तरह से इन्टर पास लड़कियों का पति पत्नी में अगर इन्टर पास है पत्नी तो देश भर के सर्वेक्षण के बाद जो रिपोर्ट आयी वह आया 1.7 और बिहार में अगर वैसा परिवार पति पत्नी में पत्नी अगर इन्टर पास है तो यहाँ आया प्रजनन दर 1.6 जो मेरे लिए तो यूरेका की परिस्थिति हो गयी और उसी समय हमने तय किया कि हम अपने यहाँ के बिहार के हर लड़की को 12वीं कक्षा तक पढ़ायेंगे और इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे अभी जान लीजिये 6 हजार तक जो भी होना बहुत हो चुका है । अब जो बचा हुआ है उन सभी पंचायतों में इसी साल- यह है फरवरी और अप्रैल महीने से वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय का काम शुरू होगा 9वीं की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी और उसके लिए सारा काम हो रहा है । 450 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए ताकि दो-दो कमरा बन जाय । लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बन जाय । उसके लिए और जो सुविधाायें होती हैं वह सब किया जाय । यह सारा काम हो जायेगा तो पूरे तौर पर यह सब काम है और शिक्षा के विकास के लिए आपको मालूम है कि बांका में उन्नयन योजना की शुरुआत की गयी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो उन्नयन बांका का कार्यक्रम था 9वें और 10वें क्लास के लिए स्मार्ट कक्ष स्थापित कर छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था हम भी देखने गए और हम देखे हमको बहुत अच्छा लगा वह तो दो सब्जेक्ट का कर रहा था, हमने कहा दो नहीं पूरे पॉच सब्जेक्ट का करो और पूरे पॉच सब्जेक्ट का उसने करना शुरू किया और उसके बाद कहा कि यह पूरे बिहार के लिए उन्नयन कार्यक्रम शुरू हो गया । यह पूरे बिहार में उन्नयन कार्यक्रम शुरू करा दिया गया और अब स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । 38 जिलों में 5 सितम्बर से जो आप जानते हैं शिक्षक दिवस है । 5 सितम्बर,

2019 से पूरे बिहार में यह उन्नयन स्कीम हमलोगों ने चालू कर दिया है । उन्नयन बिहार स्कीम और 5 विषयों में अध्यापन का कार्यक्रम इस पर कराया जा रहा है । इसके अलावे हमने एक सुझाव और दिया है कि यह जो सबसे खतरनाक और गंदी चीज जो दुनिया में आयी है । वह है पोर्न-साईट । गंदी चीज लोग देख रहे हैं । आजकल मोबाईल का इतना यूज हो गया है और इतनी घटिया चीज दुनिया भर में चलती है, जो छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है । ये इसी तरह का चीज लोग देख लेते हैं बहुत लोग और उसके चलते --(व्यवधान) हॉ उसको जाना चाहिए, यह अलग बात है । अरे भाई, यहॉ का काई एम.एल.ए. तो नहीं न देखता है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कर्णाटक के डिप्टी सी.एम. बन गए हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अरे, वह तो आप बोलियेगा । अरे हम तो सलाह दे रहे हैं हमारा सलाह तो सुनिये । हमारा सलाह सुनिये । पोर्न-साईट पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमलोगों ने राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया है और आप जान लीजिये यह जो उन्नयन बिहार स्कीम है उसमें पॉच विषय को हमलोगों ने शुरू किया है अब उसके साथ-साथ हमने एडवाईस दिया है कि उनलोगों को बच्चे-बच्चियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दो और पोर्न-साईट कोई नहीं देखे, उस पर नहीं जाय, इसका भी उसमें अवेयरनेस लाने का प्रयास हम लोग करेंगे ताकि आज जो कई प्रकार (व्यवधान) बैन लगाने के लिए लिखा है यह तो सारी बात है बैन लगाने की बात हम बराबर कह रहे हैं, एकदम बैन होना चाहिए तो इसलिए हर प्रकार से हमलोगों ने यह सब काम प्रारम्भ करवाया है, प्रारम्भ कर रहे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आप जानते हैं कि जिस तरह से हर तरह से छात्रावास अनुदान से लेकर सब तरह से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पहले 25 करोड़ किए थे, अब बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया । स्वरोजगार हेतु 14,353 अल्पसंख्यक लाभुकों को ऋण का वितरण किया गया है और इस वर्ष इस साल 1,802 लाभुकों के बीच 36 करोड़ 97 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है और मदरसों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत की गयी है और इसमें काम भी शुरू कर दिया । 16 मदरसों का भी चयन हो गया । कई मदरसों में निर्माण कार्य शुरू हो गया और विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राज्य के 17,090 वस्तानियॉ आठवें स्तर के मदरसों में तालिमे लोबालिगान पाठ्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है इसके अंतर्गत 4 हजार शिक्षकों, 2 हजार प्रधान मौलवियों को प्रशिक्षित तथा 200 मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है । इसलिए

मदरसों के शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और इस पर राज्य सरकार 20 करोड़ रुपया खर्च कर रही है । वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करने के लिए बिहार राज्य वक्फ विकास योजना और अब तक वक्फ का चार आ गया है काम शुरू हो रहा है तो इस तरह से राज्य के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा और उसके लिए जमीन ली जा रही है । दरभंगा में तो हम काम शुरू कराके चले आए और इस प्रकार से एक चीज और जान लीजिये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम है प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मैट्रिक कमेंस योजना के अंतर्गत जो केन्द्र की योजना है अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए तो केन्द्र सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जो निर्धारित कोटा है 37,962 उससे जितने बच जाते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से यह हमलोग निर्धारित कर रहे हैं तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न:15/कृष्ण/26.02.2020

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमश :) 2019-20 में 25 करोड़ रूपये का बजट का उपबंध किया गया । 31,441 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जायेगी । तो कई प्रकार से काम 2018-19 में 40 हजार 47 छात्र-छात्राओं पर राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया तो किसी भी समुदाय के लोगों को, हर समुदाय के लोगों के लिये, हर तबके के लोगों के लिये काम कर रहे हैं । अब बताईये जल-जीवन हरियाली अभियान, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की संयुक्त बैठक जो माननीय अध्यक्ष,बिहार विधान सभा ने बुलाया था 13 जुलाई, 2019 को और उसके बाद यह तय हुआ, अब हमलोग यह सब कार्यक्रम कर रहे हैं, 11 सूत्री कार्यक्रम और सब कुछ करके कई काम किये जा रहे हैं । हम केवल आपको एक अद्यतन स्थिति बता देना चाहते हैं ।

जिला स्तर पर निरीक्षण में चिन्हित कुल 97,246 सार्वजनिक जल संचयी संरचनाओं यानी तालाब, पोखर, आहर, पईन सब 24,448 अतिक्रमित संरचनायें हैं, उनमें से 14,308 अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है । शेष 6,140 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 21,470 तालाबों में से 981 तालाबों में जिर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किये गये हैं । 142 तालाबों में जिर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है । 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले 28,109 तालाबों 6,014 तालाबों में जिर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया । 2,621 तालाबों में जिर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो रहा है । मेरा कर्त्तव्य है जो काम हो रहा है, हम आपको बता दें । ध्यान रखियेगा।

कितना तेजी से काम किया, यात्रा करके, हर जगह की स्थिति देख करके और अब इस पर काम भी प्रारंभ हो गया । तो कुल 19,243 आहरों में से 4,786 में जिर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया । 2,281 आहरों का भी जिर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया । कुल 28,444 पईनों में 7,058 में जिर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हो गया और 3,566 का जिर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया । मेरी ड्यूटी है, हम आपको बता दें और कोई गरीब-गुरबा तबका का व्यक्ति जो हमलोग पोखर तालाब सब पर अगर अगल-बगल बसा हुआ है, जिसको कुछ नहीं है तो उनको जो अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, उनको घर बनाने के लिये भी पैसा देंगे और जमीन खरीदने के लिये भी पैसा देंगे । यह भी हम लोगों ने फैसला किया है ।

रूफ टौप एरिया जो 3 हजार से अधिक क्षेत्रफल वाला छत है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है, सरकारी भवनों पर, उसका काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है । करीब-करीब शिक्षा विभाग के द्वारा 4,483 के विरूद्ध 2,081 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा कर दिया ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 560 के विरूद्ध 131 भवनों में काम पूर्ण किया गया । अन्य विभागों के द्वारा 6,610 भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया । शेष भवनों में अगले दो वित्तीय वर्षों में यह काम पूराकर लिया जायेगा ।

2019-20 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण विकास द्वारा 600 से अधिक पौधशालाओं में 5 करोड़ से अधिक पौधों को तैयार किया जा रहा है । पहले पौधा भी बाहर से लाना पड़ता था । अब तय है कि हमलोग बिहार में ही पौधा तैयार करेंगे और उसी का वृक्षारोपण करेंगे । तो इस काम के लिये 5 करोड़ से अधिक पौधों को तैयार किया जा रहा है ।

बिहार पृथ्वी दिवस जो 9 अगस्त,20 को होगा यानी 9 अगस्त,2020 को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक दिन में 9 अगस्त,20 को 2 करोड़ 51 लाख पौधा रोपण का काम किया जायेगा । जितना काम करते हैं, सब की तैयारी करते हैं, वह आपको बता दिये ।

जल-जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत, आप जान लीजिये, 218 सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रारंभ कर दी गयी है । सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है । सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है । तो इसके लिये मैंने काम शुरू कर दिया है । जो 11 कंपोनेंट हैं, उसका 10वां कंपोनेंट यही है और 11वां अभियान का है निरंतर । अभियान में तय कर दिया है अब एक बार ही नहीं, मानव श्रृंखला 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग बल्कि यह तय कर दिया कि हर महीने के पहले मंगलवार के दिन एक घंटा तक पर्यावरण पर चर्चा सभी स्कूल कॉलेज, सारे

कार्यालयों में करेंगे और एक-एक विषय पर और निर्णय यह हुआ है कि इस बार सौर ऊर्जा पर सब जगह चर्चा करेंगे और सतत् जागरूकता के लिये हमने यही कहा कि इसके अंतर्गत जो मंगलवार को करेंगे, इस योजना के अंतर्गत जन-जीवन हरियाली से संबंधित बिन्दुओं पर परिचर्चा, जितने हमारे कंपोनेंट हैं, इस पर चर्चा, फिर जल का, कृषि का, हरियाली का, सौर ऊर्जा का इससे संबंधित जितने सब कुछ हैं, पर्यावरण से संबंधित इस पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठि करेंगे, निबंधन लेखन, लोगें को प्रेरित किया जायेगा कि इस पर कुछ लिखिये और भाई मुझे तो इतनी खुशी होती है, जब हम कभी स्कूल में अपने यात्रा के दौरान गये, तब देखा और अभी हम गये, मौलाना आजाद के नाम पर जो ऊर्दू विश्वविद्यालय है, उसका दरभंगा में जो सेंटर है, वहां हम गये और हमने देखा कि दर्जनों बच्चे-बच्चियों को किस तरह से पर्यावरण के बारे में उनलोगों ने सोचा है और क्या-क्या डिमॉन्सट्रेट किया, इतना सुंदर लगा कि साहब अगर ये बात हुई, नई पीढ़ी के मन में यह बात पर्यावरण का आयेगा तभी जीवन संरक्षित होगा । उसमें हमने देखा इतना सुंदर ढंग से काम किया कि निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। सरकारी विद्यालयों के बच्चों को जल स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये बच्चों को विजिट भी कराया जायेगा कि चलों किसी नदी को दिखायेंगे, किसी तालाब को दिखायेंगे, कहीं आहर-पईन है, उसको दिखायेंगे यानी बच्चे-बच्चियों को पूरा कॉसेस करने के लिये, हर मंगलवार को, पहले मंगलवार को एक घंटा इसी पर हमलोग लगायेंगे यानी 11वां आईटम है अभियान वह सिर्फ एक बार मानव श्रृंखला के लिये नहीं, बल्कि सदैव, निरंतर चलता रहेगा ताकि लोगों को कांससनेस आये ।

(व्यवधान)

एक बात और । ठीक है । हम खत्म कर देते है । कहिये तो बैठ जाय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, 4 बज गया है ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : एक चीज और कह देते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये की जा रही है । दिनांक 19 फरवरी,2020 को हमने एक मीटिंग की और इसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी । एक वित्त मंत्री के रूप में समाज के विभिन्न तबकों के साथ बजट तैयार करने के पूर्व जो ये चर्चा करते हैं तो कृषि से संबंधित उन तबकों से इनकी बातचीत हुई । मुझको इन्होंने सूचित किया कि हम सबों को इस पर सोचना चाहिए । हमने कहा जरूर, यह अच्छी बात है । 19 फरवरी,20 को हमने बैठक बुलायी है, विभिन्न फसलों, उद्यानी फसलों, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जैविक खेती, मौसम के अनुकूल कृषि करनेवाले कृषकों के

साथ बैठक हुई और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना । यह बैठक बहुत ही प्रभावी और उपयोगी रहा है और एक निर्णय जो हमलोग कर रहे हैं जो राज्य औद्योगिक नीति,2016 है इसमें हमलोग कुछ संशोधन कर रहे हैं, उसका कुछ विस्तार कर रहे हैं उसमें भी कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का प्रबंधन क्षेत्र को शामिल करने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा रहा हळ । तो हर तरह से किसी भी चीज को पूरे ढंग से काम किया जा रहा है । तो हम इतना ही कहेंगे, वैसे तो बहुत सारे विषय हैं । मगर तीनों चले गये, अब तीनों रहते, अब समय खत्म हो गया, सिद्दिकी साहब कह रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं । हमको क्या दिक्कत है । कहियेगा कि बोलिये तो हम बोलते रहेंगे । हमको कोई एतराज नहीं है । लेकिन और विष्य पर भी चर्चा होती । उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । चर्चा होगी, अनेक बार चर्चा होगी । तो मैं पुनः यही कहूंगा कि हमलोगों की पूरी प्रतिबद्धता है

क्रमश :

टर्न–16/राजेश/26.2.20

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः समाज की सेवा में, समाज के हर तबके के उत्थान में, बिहार के हर इलाके के विकास में, न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता है और यह काम पूरी श्रद्धा के साथ हम सब इस काम को करते रहते हैं, इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसके लिए उनको हम सब धन्यवाद ज्ञापित करें, यही निवेदन करते हुए, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद लेकिन उस पर गौर कीजियेगा, तो बहुत अच्छा होगा, सब के हक में है, सब के हित में है, हमने कोई राजनैतिक रुप से किसी बात को नहीं रखा है, हमने इसको व्यवहारिक तौर पर और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कुछ भी हमलोगों की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसको एक हद तक जानकारी दी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हुए यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें ।

अध्यक्षः सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डा0 रंजु गीता द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संशोधनों पर विमर्श हुआ है । अब मैं एक–एक करके संशोधन को और मूल प्रस्ताव को लूंगा । क्या माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, जो हमलोगों ने संशोधन दिया है, हम चाहेंगे कि इसमें रहे और हम इसे वापस नहीं लेंगे और अभी मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बातों को रखा, कई योजना तो 7 निश्चय जैसी योजना है और यह तो महागठबंधन सरकार की थी,जब हमलोग सरकार में थे । महोदय, कई बातें इन्होंने बताया, डी0जी0पी0 की बातें कहीं, क्राईम की बातें कहीं लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ ? बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का क्या हुआ, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, बेरोजगारों का क्या हुआ, 7 करोड़ नौजवानों पर कोई जवाब नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का क्या हुआ..... ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः आप वापस नहीं लेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः जी नहीं लेंगे । एकदम से नहीं लेंगे ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ है ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-25 है, अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....

परिशिष्ट–1

बुलेट प्वाइंट

1. राज्य की नौकरियों के 85 प्रतिशत बिहार राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित किया जाय। अनुसूचित जातियों जनजातियों, पिछड़े और अतिपिछड़ों वर्गों के आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जाएगा। अब जबकि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा समाप्त हो चुकी है राज्य में प्रत्येक वर्ग एवं जाति के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर उनके जातिगत जनसंख्या के आधार पर की जाय।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों यथा मेडिकल, इंजिनीयरिंग, कृषि एवं वेटनरी संस्थानों के स्नातक/पारास्नातक के 50 प्रतिशत सीटों जिसपर केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार की एजेन्सियाँ सीटों का आवंटन करती है, उन सीटों पर EWS, SC/ST कि के साथ-साथ नियमानुसार पिछड़े-अतिपिछड़े को भी लाभ दिया जाए
3. आरक्षण के प्रावधानों को संविधान के अनुसूची-IX में शामिल करने हेतु विधान मंडल से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा जाए
4. सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरे जाए। स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जाय। नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन लागू नहीं किया गया है। कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर, टोला सेवकों, ममता कर्मियों, आशा कर्मियों, विकास मित्रों, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ सभी को स्थाई करते हुए वेतनमान दिया जाय। टी0ई0टी0/उर्दू टी0ई0टी0 पास अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाय
5. ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर-मजदूरों और अन्य पेशागत समूहों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये । राज्य में अविलम्ब खेत मजदूरों और असम्बध मजदूरों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर जिंदगी जीने हेतु कारगर कदम उठाये जायें । परम्परागत पेशे से जुड़े बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर, धुनकर, चूड़ीबाल, मछुआ, चौरसिया, कामगार, पासी चमार एवं रंगरेज भाईयों को उनके आर्थिक विकास के साधन दिये जायें एवं समूह बीमा एवं रोजगार हेतु बिना ब्याज के राशि उपलब्ध कराया जाय।
6. बिहार में आई.टी सेक्टर का हब बनाया जाए।
7. राज्य की सभी परीक्षा समय पर और बिना धांधली की करायी जाए।
8. सरकारी यूनिवर्सिटी/कॉलेजों के साथ-साथ प्राईवेट कॉलेज/यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए।
9. बंद पड़े पुराने फैक्ट्रियों/मिलों को चालू कराये जाए, नए-नए फैक्ट्री खोले जाए, टूरिस्ट सेन्टर बनाया जाए
10. **(विधि व्यवस्था)** राज्य में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों पर वीभत्स अत्याचार, उनके जमीन पर कब्जा हो रही है। गरीबों-दलितों को पुलिसिया तंत्र द्वारा तंग नहीं किया जाये। ऐसे दमनकारी ताकतों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाय। सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के आन्दोलन से कमजोर और अभिवंचित वर्गों में आयी सामाजिक राजनीतिक चेतना को विकसित करने और उसे मूर्तरूप देने का ठोस कार्यक्रम बनाया जाये

परिशिष्ट–2

प्रखंड कार्यालय भगवानपुर।
पत्रांक 1923 दिनांक 19.09.2019

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
भगवानपुर।

सेवा में,

थानाध्यक्ष
भगवानपुर।

विषय :– प्रथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि माननीय विधायक श्री रामदेव राय द्वारा प्रखंड में शौचालय (लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान) के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में गंभीर धांधली की शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा से की गयी है जिसमे प्रखंड समन्वयक भगवानपुर श्री विजय कुमार गुप्ता के द्वारा अनेका–अनेक लाभुकों से रिश्वत के तौर पर दो–दो हजार रूपये वसूल करना , पंचायतों में बेरोजगार युवकों से जियो टैगिंग करा कर छः–छः माह तक पैसा नहीं दिया जाना ,लाभुकों से पैसा उगाही करना , एवं लाभुको खाते में भुगतान की बात करने पर गाली–गलौज एवं दिखा देने की धमकी देना इत्यादि है जिसके साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा दस्तावेज एवं ऑडियो क्लीप भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय विधायक के द्वारा दियें गये शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा द्वारा मामले की जांच कर उनके पत्रांक 350/गो0 दिनांक 17.09.2019 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन निर्गत करते हुए दोषी व्यक्ति प्रखंड समन्वयक भगवानपुर श्री विजय कुमार गुप्ता के बिरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निदेशित किया गया है। (जांच प्रतिवेदन की प्रति साक्ष्य सहित संलग्न)

अतः अनुरोध है कि श्री विजय कुमार गुप्ता प्रखंड समन्वयक भगवानपुर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु0– यथोक्त

विश्वासभाजन
19/9/19
प्रखंड विकास पदाधिकारी
भगवानपुर।

Registered Bhagwanpur PS case No-170/19 dated 19/9/19 u/s 420/504 506 IPC & 66(D) I.T Act & will investigate the case.

Binod
19/9/19
S.H.O
Bhagwanpur PS

अजय कुमार
पिता- श्री बाबूलाल राय
ग्राम - सदरपुर
पो० - अमावा
थाना - बिन्द
जिला - नालन्दा

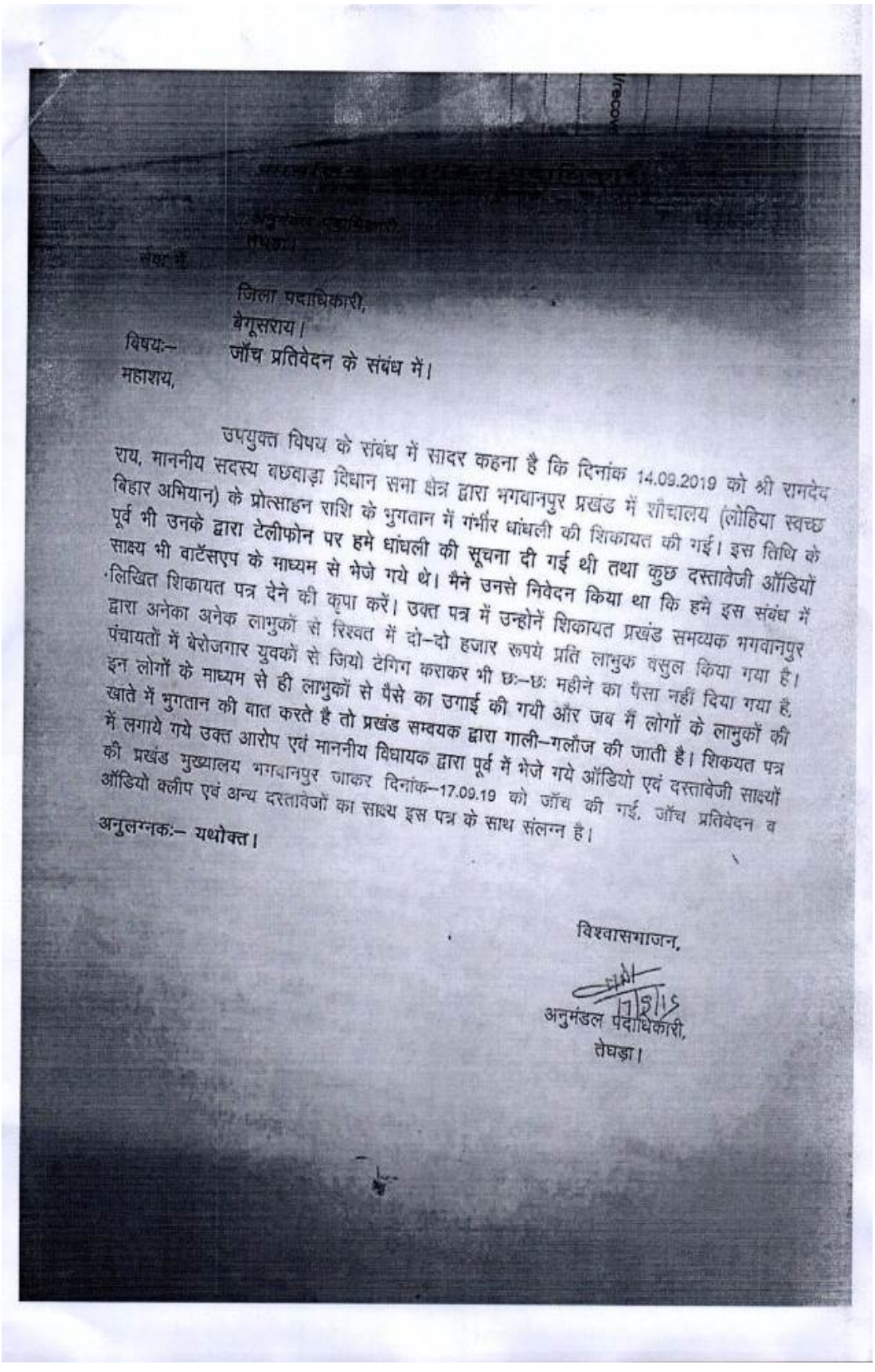

अनुमंडल पदाधिकारी,
तेघड़ा।

संवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

विषयः– जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में सादर कहना है कि दिनांक 14.09.2019 को श्री रामदेव राय, माननीय सदस्य बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वारा भगवानपुर प्रखंड में शौचालय (लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान) के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में गंभीर धांधली की शिकायत की गई। इस तिथि के पूर्व भी उनके द्वारा टेलीफोन पर हमे धांधली की सूचना दी गई थी तथा कुछ दस्तावेजी ऑडियों साक्ष्य भी वाटॅसएप के माध्यम से भेजे गये थे। मैने उनसे निवेदन किया था कि हमे इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र देने की कृपा करें। उक्त पत्र में उन्होनें शिकायत प्रखंड समव्यक भगवानपुर द्वारा अनेका अनेक लाभुकों से रिश्वत में दो–दो हजार रूपये प्रति लाभुक वसुल किया गया है। पंचायतों में बेरोजगार युवकों से जियो टेगिंग कराकर भी छः–छः महीने का पैसा नहीं दिया गया है, इन लोगों के माध्यम से ही लाभुकों से पैसे का उगाई की गयी और जब मैं लोगों के लानुकों की खाते में भुगतान की बात करते है तो प्रखंड समव्यक द्वारा गाली–गलौज की जाती है। शिकयत पत्र में लगाये गये उक्त आरोप एवं माननीय विधायक द्वारा पूर्व में भेजे गये ऑडियो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर जाकर दिनांक–17.09.19 को जाँच की गई. जाँच प्रतिवेदन व ऑडियो क्लीप एवं अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17/9/19

अनुमंडल पदाधिकारी,
तेघड़ा।

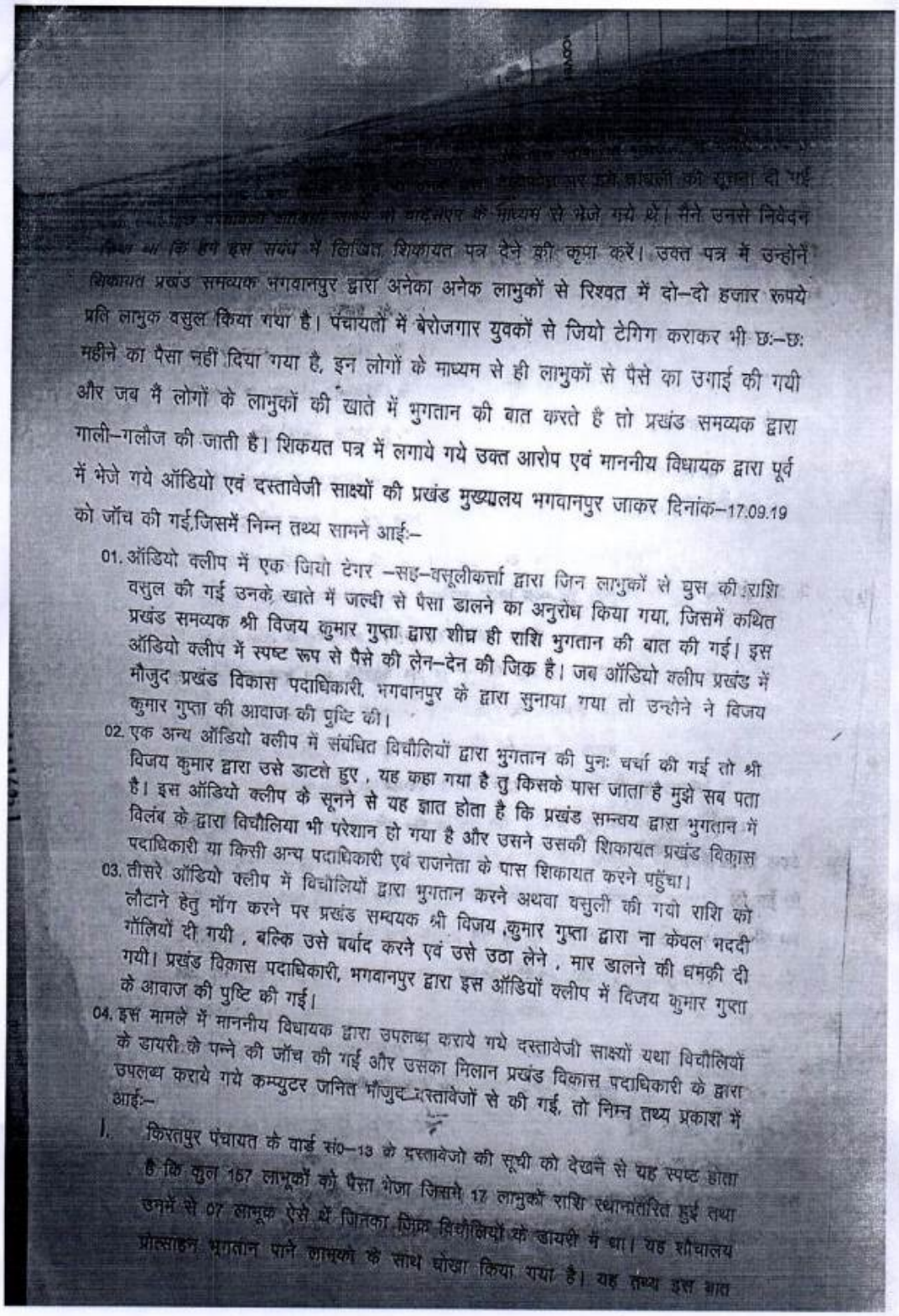

[illegible] सूचना दी गई [illegible] के माध्यम से भेजे गये थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमें इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र देने की कृपा करें। उक्त पत्र में उन्होंने शिकायत प्रखंड समव्यक भगवानपुर द्वारा अनेका अनेक लाभुकों से रिश्वत में दो–दो हजार रूपये प्रति लाभुक वसुल किया गया है। पंचायतों में बेरोजगार युवकों से जियो टेगिंग कराकर भी छः–छः महीने का पैसा नहीं दिया गया है, इन लोगों के माध्यम से ही लाभुकों से पैसे का उगाई की गयी और जब मैं लोगों के लाभुकों की खाते में भुगतान की बात करते है तो प्रखंड समव्यक द्वारा गाली–गलौज की जाती है। शिकयत पत्र में लगाये गये उक्त आरोप एवं माननीय विधायक द्वारा पूर्व में भेजे गये ऑडियो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर जाकर दिनांक–17.09.19 को जॉच की गई,जिसमें निम्न तथ्य सामने आई:–

01. ऑडियो क्लीप में एक जियो टेगर –सह–वसूलीकर्त्ता द्वारा जिन लाभुकों से घुस की राशि वसुल की गई उनके खाते में जल्दी से पैसा डालने का अनुरोध किया गया, जिसमें कथित प्रखंड समव्यक श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा शीघ्र ही राशि भुगतान की बात की गई। इस ऑडियो क्लीप में स्पष्ट रूप से पैसे की लेन–देन की जिक है। जब ऑडियो क्लीप प्रखंड में मौजुद प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर के द्वारा सुनाया गया तो उन्होंने ने विजय कुमार गुप्ता की आवाज की पुष्टि की।
02. एक अन्य ऑडियो क्लीप में संबंधित बिचौलियों द्वारा भुगतान की पुनः चर्चा की गई तो श्री विजय कुमार द्वारा उसे डाटते हुए , यह कहा गया है तु किसके पास जाता है मुझे सब पता है। इस ऑडियो क्लीप के सूनने से यह ज्ञात होता है कि प्रखंड सम्न्वय द्वारा भुगतान में विलंब के द्वारा बिचौलिया भी परेशान हो गया है और उसने उसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी एवं राजनेता के पास शिकायत करने पहुँचा।
03. तीसरे ऑडियो क्लीप में बिचौलियों द्वारा भुगतान करने अथवा वसुली की गयो राशि को लौटाने हेतु मॉग करने पर प्रखंड सम्वयक श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा ना केवल भददी गॉलियों दी गयी , बल्कि उसे बर्बाद करने एवं उसे उठा लेने , मार डालने की धमकी दी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर द्वारा इस ऑडियों क्लीप में विजय कुमार गुप्ता के आवाज की पुष्टि की गई।
04. इस मामले में माननीय विधायक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों यथा बिचौलियों के डायरी के पन्ने की जॉच की गई और उसका मिलान प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्युटर जनित मौजुद दस्तावेजों से की गई, तो निम्न तथ्य प्रकाश में आई:–

I. किरतपुर पंचायत के वार्ड सं0–13 के दस्तावेजो की सूची को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कुल 157 लाभूकों को पैसा भेजा जिसमे 17 लाभुकों राशि स्थानांतरित हुई तथा उनमें से 07 लाभूक ऐसे थे जिनका जिक्र बिचौलियों के डायरी में था। यह शौचालय प्रोत्साहन भुगतान पाने लाभूकों के साथ धोखा किया गया है। यह तथ्य इस बात

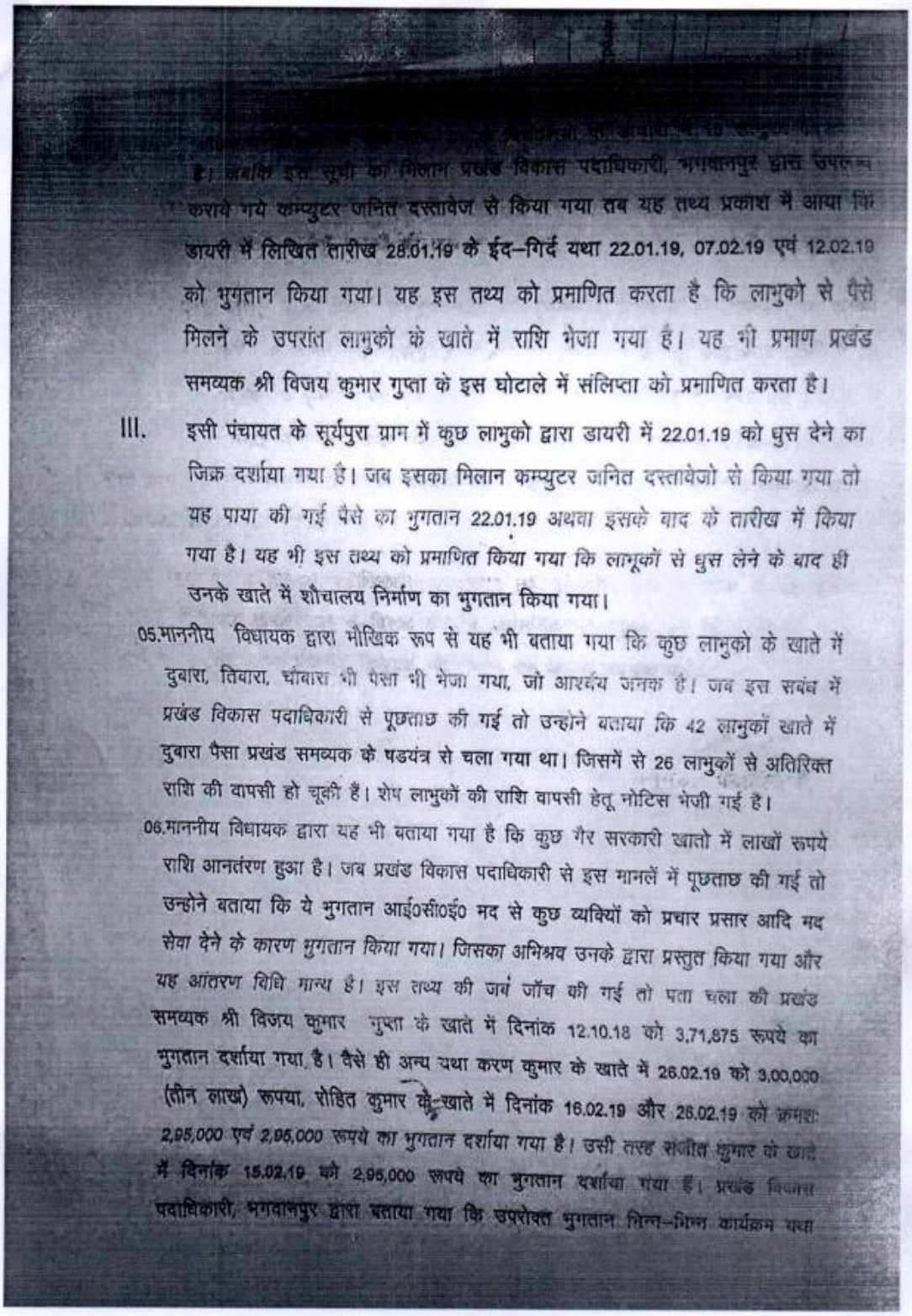

है। जबकि इस सूची का मिलान प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्युटर जनित दस्तावेज से किया गया तब यह तथ्य प्रकाश में आया कि डायरी में लिखित तारीख 28.01.19 के ईद–गिर्द यथा 22.01.19, 07.02.19 एवं 12.02.19 को भुगतान किया गया। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि लाभुको से पैसे मिलने के उपरांत लाभुकों के खाते में राशि भेजा गया है। यह भी प्रमाण प्रखंड समव्यक श्री विजय कुमार गुप्ता के इस घोटाले में संलिप्ता को प्रमाणित करता है।

III. इसी पंचायत के सूर्यपुरा ग्राम में कुछ लाभुको द्वारा डायरी में 22.01.19 को घुस देने का जिक्र दर्शाया गया है। जब इसका मिलान कम्प्युटर जनित दस्तावेजो से किया गया तो यह पाया की गई पैसे का भुगतान 22.01.19 अथवा इसके बाद के तारीख में किया गया है। यह भी इस तथ्य को प्रमाणित किया गया कि लाभूकों से घुस लेने के बाद ही उनके खाते में शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया।

05.माननीय विधायक द्वारा मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि कुछ लाभुको के खाते में दुबारा, तिबारा, चौबारा भी पैसा भी भेजा गया, जो आश्चर्य जनक है। जब इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि 42 लाभुकों खाते में दुबारा पैसा प्रखंड समव्यक के षडयंत्र से चला गया था। जिसमें से 26 लाभुकों से अतिरिक्त राशि की वापसी हो चूकी हैं। शेष लाभुकों की राशि वापसी हेतू नोटिस भेजी गई है।

06.माननीय विधायक द्वारा यह भी बताया गया है कि कुछ गैर सरकारी खातो में लाखों रूपये राशि आनतंरण हुआ है। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस मामलें में पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि ये भुगतान आई0सी0ई0 मद से कुछ व्यक्यिों को प्रचार प्रसार आदि मद सेवा देने के कारण भुगतान किया गया। जिसका अभिश्रय उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह आंतरण विधि मान्य है। इस तथ्य की जब जॉच की गई तो पता चला की प्रखंड समव्यक श्री विजय कुमार गुप्ता के खाते में दिनांक 12.10.18 को 3,71,875 रूपये का भुगतान दर्शाया गया है। वैसे ही अन्य यथा करण कुमार के खाते में 26.02.19 को 3,00,000 (तीन लाख) रूपया, रोहित कुमार के खाते में दिनांक 16.02.19 और 26.02.19 को क्रमशः 2,95,000 एवं 2,95,000 रूपये का भुगतान दर्शाया गया है। उसी तरह संजीत कुमार के खाते में दिनांक 15.02.19 को 2,95,000 रूपये का भुगतान दर्शाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर द्वारा बताया गया कि उपरोक्त भुगतान भिन्न–भिन्न कार्यक्रम यथा

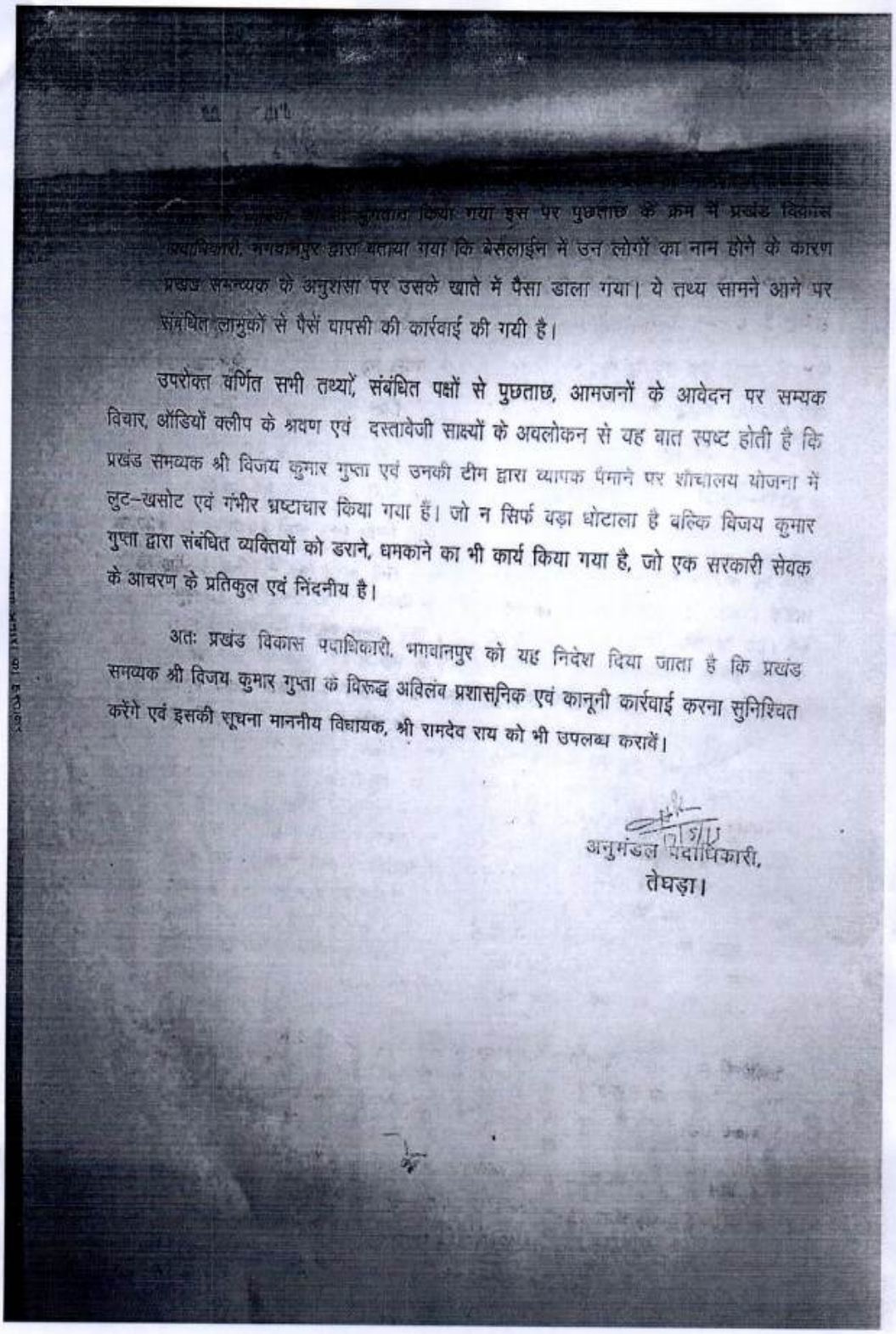

[illegible] भुगतान किया गया इस पर पुछताछ के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर द्वारा बताया गया कि बेसलाईन में उन लोगों का नाम होने के कारण प्रखंड समन्वयक के अनुशंसा पर उसके खाते में पैसा डाला गया। ये तथ्य सामने आने पर संबंधित लाभुकों से पैसं वापसी की कार्रवाई की गयी है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, संबंधित पक्षों से पुछताछ, आमजनों के आवेदन पर सम्यक विचार, ऑडियों क्लीप के श्रवण एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रखंड समव्यक श्री विजय कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा व्यापक पैमाने पर शौचालय योजना में लुट-खसोट एवं गंभीर भ्रष्टाचार किया गया हैं। जो न सिर्फ बड़ा घोटाला है बल्कि विजय कुमार गुप्ता द्वारा संबंधित व्यक्तियों को डराने, धमकाने का भी कार्य किया गया है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकुल एवं निंदनीय है।

अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर को यह निदेश दिया जाता है कि प्रखंड समव्यक श्री विजय कुमार गुप्ता के विरूद्ध अविलंब प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना माननीय विधायक, श्री रामदेव राय को भी उपलब्ध करावें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
तेघड़ा।